गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 264
दि. 25.01.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

वैश्विक पटल पर भारत की सख़्त दस्तक

भगोड़ों के लिए सिमटी दुनिया, जांच एजेंसियों ने कसा अंतरराष्ट्रीय शिकंजा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। अपराध करके देश छोड़ देना और विदेशों में सुरक्षित जीवन बिताना—यह सोच अब तेजी से अतीत की बात बनती जा रही है। बीते एक साल में भारतीय जांच एजेंसियों ने जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भगोड़ों के खिलाफ मोर्चा खोला है, उसने यह साफ कर दिया है कि कानून से भागना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 इस बात की गवाही देती है कि भारत की जांच और खुफिया एजेंसियां न केवल मजबूत हुई हैं, बल्कि उनकी वैश्विक पहुंच भी पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी हो चुकी है।

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक साल में विदेशों में छिपे 70 से ज्यादा वांछित अपराधियों और भगोड़ों को भारतीय एजेंसियों ने सफलतापूर्वक ट्रेस किया है। यह आंकड़ा अपने आप में ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि पिछले एक दशक में किसी एक वर्ष में इतनी बड़ी संख्या में भगोड़ों की पहचान नहीं हो पाई थी। अधिकारियों का मानना है कि यह उपलब्धि भारत के बढ़ते कूटनीतिक प्रभाव, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी क्षमताओं का प्रत्यक्ष परिणाम है। अब अपराधी चाहे किसी भी देश में छिपे हों, उनकी गतिविधियों पर नजर रखना और उन्हें कानून के दायरे में लाना भारत के लिए संभव होता जा रहा है। यह कार्रवाई सिर्फ भारतीय भगोड़ों तक सीमित नहीं रही। भारत ने यह भी दिखाया कि वह अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निभा रहा है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इसी अवधि में भारत में छिपे हुए दूसरे देशों के 203 वांछित अपराधियों को भी ट्रेस किया गया। इसका मतलब यह है कि भारत न केवल अपने नागरिकों द्वारा किए गए अपराधों पर नजर रख रहा है, बल्कि अपनी जमीन को किसी भी तरह से अंतरराष्ट्रीय अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनने से रोकने के लिए भी सख्त कदम उठा रहा है। वैश्विक पुलिसिंग और कानून व्यवस्था में यह भारत की भूमिका को एक जिम्मेदार और भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित करता है।

सबसे अहम उपलब्धि उन मामलों में सामने आई है, जहां अपराधियों को सिर्फ ढूंढा ही नहीं गया, बल्कि उन्हें भारत वापस लाने में भी सफलता मिली। पिछले वित्तीय वर्ष में कुल 27 भगोड़ों को विदेशों से भारत प्रत्यर्पित या निर्वासित किया गया। इन मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच मजबूत तालमेल देखने को मिला। इंटरपोल की नोडल एजेंसी के रूप में सीबीआई ने कई देशों की पुलिस और न्यायिक संस्थाओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा, जिससे यह सुनिश्चित हो सका कि कानूनी प्रक्रियाएं समय पर पूरी हों और अपराधी कानून से बच न सकें। विदेशी न्यायिक प्रणालियों से सहयोग हासिल करने में 'लेटर्स रोगेटरी' यानी एलआर की भूमिका भी बेहद अहम रही। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच भारत ने कुल 74 लेटर्स रोगेटरी भेजे, जिनमें से 54 सीधे तौर पर सीबीआई से जुड़े थे, जबकि 20 राज्य पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के थे। इनमें से 47 अनुरोधों पर पूरी कार्यवाही हो चुकी है, जो यह दर्शाता है कि विदेशी अदालतों और जांच एजेंसियों के साथ भारत का समन्वय पहले से कहीं अधिक बेहतर हुआ है। हालांकि, प्रक्रिया की जटिलता और विभिन्न देशों के अलग-अलग कानूनी ढांचे के कारण कई मामलों में समय लगता है, फिर भी यह प्रगति अपने आप में उल्लेखनीय है।

सफलताओं के बीच चुनौतियां भी कम नहीं हैं। 31 मार्च 2025 तक भारत के कुल 533 कानूनी अनुरोध विभिन्न देशों में लंबित हैं। इनमें 276 मामले सीबीआई से जुड़े हैं, जबकि 257 अन्य एजेंसियों के हैं। यह संख्या बताती है कि अंतरराष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ लड़ाई लंबी और जटिल है। दिलचस्प बात यह है कि यह सहयोग एकतरफा नहीं है। भारत को भी विदेशी एजेंसियों से करीब 32 कानूनी अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिन पर भारतीय एजेंसियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। यह परस्पर सहयोग वैश्विक कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

भगोड़ों पर दबाव बनाने के लिए इंटरपोल नोटिसों का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। एनसीबी-इंडिया ने इस वर्ष 126 रेड नोटिस जारी किए, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिरफ्तारी के लिए सबसे प्रभावी माध्यम माने जाते हैं। इसके अलावा संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 89 ब्लू नोटिस और लापता लोगों की तलाश के लिए 24 येलो नोटिस जारी किए गए। इन नोटिसों के जरिए न केवल अपराधियों की पहचान और लोकेशन साझा की जाती है, बल्कि उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया जाता है कि वे कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। इंटरपोल के माध्यम से समाज के लिए खतरा बनने वाले अन्य तत्वों पर भी नजर रखी गई है। अज्ञात शवों की पहचान के लिए 7 ब्लैक नोटिस जारी किए गए, जबकि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा बन सकने वाले अपराधियों के खिलाफ 1 ग्रीन नोटिस जारी हुआ। इन सभी कदमों का मकसद यही है कि अपराधियों को यह एहसास कराया जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमाएं अब उनके लिए ढाल नहीं बन सकतीं। इस पूरी कवायद के केंद्र में सीबीआई का ग्लोबल ऑपरेशंस सेंटर अहम भूमिका निभा रहा है। यह सेंटर विदेशी पुलिस एजेंसियों और इंटरपोल के साथ चौबीसों घंटे संपर्क में रहता है।

मतदाता सूची से लेकर संविधान तक पर सवाल,राहुल गांधी का तीखा आरोप

चुनाव आयोग लोकतंत्र का रक्षक नहीं, साजिश का हिस्सा बनता जा रहा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि आयोग अब लोकतंत्र का रक्षक नहीं रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात में चल रही एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया के जरिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के समर्थक मतदाताओं को सुनियोजित ढंग से मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि संविधान प्रदत्त 'एक व्यक्ति, एक वोट' के अधिकार को कमजोर करने की सोची-समझी साजिश है। राहुल गांधी ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी लोकतंत्र को मजबूत करना है, लेकिन मौजूदा हालात में वह सत्ता के दबाव में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन इलाकों में सत्तारूढ़ दल को हार का डर है, वहां मतदाता सूची में गड़बड़ियां की जा रही हैं और खास तौर पर कांग्रेस समर्थकों के नाम चुन-चुनकर हटाए जा रहे हैं। राहुल गांधी के मुताबिक, यह पैटर्न नया नहीं है, बल्कि पहले भी अन्य राज्यों में अपनाया जा चुका है और अब इसे गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में दोहराया जा रहा है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं का मकसद मूल रूप से मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना होता है, लेकिन इसे राजनीतिक हथियार में बदल दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के तहत बड़े पैमाने पर बिना ठोस कारणों के नाम हटाए जा रहे हैं, जिससे आम नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार छीना जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद मतदाता की स्वतंत्र इच्छा पर टिकी होती है, और अगर वही मतदाता सूची से गायब कर दिए जाएं, तो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। कांग्रेस की ओर से यह भी दावा किया गया कि मतदाता सूची संशोधन के दौरान निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का खुलेआम उल्लंघन किया गया। पार्टी नेताओं के अनुसार, कई मामलों में बिना उचित सत्यापन और सूचना के नाम काट दिए गए, जबकि आपत्तियां दर्ज कराने के बावजूद चुनाव आयोग ने समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस का आरोप है कि आयोग की यह चुप्पी इस बात का संकेत है कि वह निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभाने में विफल हो रहा है। राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे को सिर्फ एक राज्य या एक पार्टी तक सीमित न बताते हुए कहा कि यह देश के लोकतांत्रिक ढांचे से जुड़ा गंभीर सवाल है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मतदाता सूची में इस तरह की कथित हेराफेरी को रोका नहीं गया, तो इसका असर आने वाले सभी चुनावों पर पड़ेगा और आम जनता का भरोसा लोकतांत्रिक संस्थाओं से उठ सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर जनता का विश्वास बना रहना बेहद जरूरी है, लेकिन मौजूदा हालात उस विश्वास को कमजोर कर रहे हैं।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो कानूनी रास्ता भी अपनाया जाएगा। पार्टी का दावा है कि वह हर उस मतदाता के साथ खड़ी है, जिसका नाम गलत तरीके से सूची से हटाया गया है। कांग्रेस का तर्क है कि लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे नागरिकों के अधिकारों और संविधान की आत्मा की अभिव्यक्ति होते हैं।

इस बीच, राहुल गांधी के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने भी मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता की मांग की है, जबकि सत्तारूढ़ पक्ष की ओर से इन आरोपों को खारिज किया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक राहुल गांधी के आरोपों पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इस तरह के आरोप लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख पर असर डालते हैं और इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। कुल मिलाकर, राहुल गांधी का यह बयान एक बार फिर चुनावी प्रक्रियाओं की निष्पक्षता, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और मतदाता अधिकारों को लेकर देशव्यापी बहस को हवा दे गया है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि चुनाव आयोग इन आरोपों पर क्या रुख अपनाता है और क्या मतदाता सूची से जुड़े विवादों का कोई पारदर्शी समाधान सामने आता है या नहीं।

आवारा कुत्तों की हत्या पर उबाल,तेलंगाना में 900 मौतों के आरोप, पंचायत प्रतिनिधियों पर कानून के शिकंजे की तैयारी

(जीएनएस)। हैदराबाद। तेलंगाना में आवारा कुत्तों की कथित सामूहिक हत्या का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। जगतियाल जिले में सामने आई ताजा घटना ने पूरे राज्य में आक्रोश फैला दिया है। पशु अधिकार संगठनों के अनुसार, जिले के अलग-अलग गांवों में अब तक करीब 900 आवारा कुत्तों को मारे जाने का आरोप है, जबकि हालिया मामला पेगाडापल्ली गांव से जुड़ा है, जहां 22 जनवरी को लगभग 300 कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन देकर मार डालने की शिकायत दर्ज कराई गई है। इस घटना के बाद न सिर्फ स्थानीय स्तर पर, बल्कि राज्यभर में पशु प्रेमियों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस जघन्य कृत्य के पीछे ग्राम सरपंच और ग्राम पंचायत सचिव की भूमिका है। आरोप है कि सरपंच ने आवारा कुत्तों को मारने के लिए कुछ लोगों को काम पर लगाया और उन्हें जहरीले इंजेक्शन देकर कुत्तों की हत्या करवाई गई। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह कोई अलग-थलग घटना नहीं है, बल्कि पिछले कई महीनों से जिले के अलग-अलग इलाकों में इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं, जिन पर अब तक गंभीर कार्रवाई नहीं हुई थी। उनका दावा है कि दिसंबर में हुए ग्राम पंचायत चुनावों से पहले ग्रामीणों से किए गए वादों को पूरा करने के दबाव में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों ने यह अमानवीय रास्ता अपनाया।

पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए शिकायत के आधार पर ग्राम सरपंच और पंचायत सचिव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और यदि आरोप सही पाए गए तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस तरह की हत्याएं किसी संगठित तरीके से की गईं और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल थे।

इस घटना ने ग्रामीण इलाकों में आवारा कुत्तों की समस्या और उससे निपटने के तरीकों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों के हमलों और डर की वजह से ग्रामीण लंबे समय से परेशान थे, लेकिन इसका समाधान कानून और मानवीय तरीकों से निकाला जाना चाहिए था। पशु अधिकार संगठनों का तर्क है कि नसबंदी, टीकाकरण और पुनर्वास जैसे उपाय मौजूद हैं, जिन्हें अपनाने के बजाय सीधे हत्या का रास्ता चुनना कानून का खुला उल्लंघन है।

पशु कल्याण संगठनों ने राज्य सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। संगठनों का यह भी कहना है कि अगर इस तरह के मामलों पर सख्ती नहीं दिखाई गई तो यह एक खतरनाक मिसाल बन सकती है, जहां जनदबाव या राजनीतिक लाभ के लिए कानून और मानवीय मूल्यों को ताक पर रख दिया जाएगा।

इस बीच, राज्य के राजनीतिक गलियारों में भी यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। विपक्षी दलों ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि स्थानीय निकायों को आवारा पशुओं के प्रबंधन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और संसाधन नहीं दिए गए, जिसके चलते ऐसे अमानवीय कदम उठाए गए। वहीं, सरकार की ओर से कहा गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में सामने आया यह मामला सिर्फ पशु क्रूरता का नहीं, बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी, कानून के पालन और मानवीय संवेदनाओं की भी परीक्षा है। आने वाले दिनों में जांच की दिशा और सरकार की कार्रवाई यह तय करेगी कि इस तरह की घटनाओं पर वास्तव में रोक लग पाएगी या नहीं। फिलहाल, 900 आवारा कुत्तों की मौत के आरोप ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है और न्याय की मांग लगातार तेज होती जा रही है।

बजट सत्र में उठेगी सांसद इंजीनियर रशीद की आवाज, अदालत ने दी कस्टडी पैरोल की मंजूरी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। जेल में बंद लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद को संसद के आगामी बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को बड़ा आदेश पारित करते हुए उन्हें कस्टडी पैरोल प्रदान की, जिससे वह 28 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे। अदालत के इस फैसले को संसदीय लोकतंत्र और निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा की अदालत ने स्पष्ट किया कि इंजीनियर रशीद को यह अनुमति पहले से निर्धारित शर्तों के अधीन दी जा रही है। विशेष रूप से यात्रा खर्च और सुरक्षा से जुड़ी शर्तों का पालन अनिवार्य होगा। अदालत ने कहा कि कस्टडी पैरोल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सांसद अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें, साथ ही न्यायिक प्रक्रिया और कानून-व्यवस्था से कोई समझौता न हो।

सुनवाई के दौरान इंजीनियर रशीद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विख्यात ओबेरॉय ने अदालत को अवगत कराया कि यात्रा खर्च को लेकर दायर अपील अभी दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। उन्होंने दलील दी कि रशीद एक निर्वाचित सांसद हैं और संसद में उनकी उपस्थिति उनके मतदाताओं की आवाज को सामने रखने के लिए आवश्यक है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि इससे पहले भी अदालत ने इसी तरह की परिस्थितियों में रशीद को संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दी है और उन्होंने सभी शर्तों का पालन किया है।

अदालत ने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कहा कि पूर्व में दी गई कस्टडी पैरोल के दौरान किसी प्रकार की शर्तों का उल्लंघन सामने नहीं आया है। इसी आधार पर अदालत ने एक बार फिर उन्हें बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति दी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि रशीद को पूरे समय कड़ी सुरक्षा और निगरानी में रखा जाएगा और सत्र समाप्त होते ही उन्हें पुनः हिरासत में लौटना होगा।

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब इंजीनियर रशीद को संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मिली हो। इससे पहले नवंबर 2025 में अदालत ने उन्हें संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सभी तिथियों पर कस्टडी पैरोल दी थी। वहीं, 24 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक चले मानसून सत्र में भी उन्हें सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी। इन दोनों अवसरों पर रशीद ने संसद में उपस्थिति दर्ज कराई थी और अदालत द्वारा तय सभी शर्तों का पालन किया था।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अदालत का यह फैसला लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है और वहां चुने हुए प्रतिनिधियों की उपस्थिति जनता की आवाज को मजबूती देती है। ऐसे में, अदालतों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना कि कानूनी प्रक्रिया के तहत निर्वाचित प्रतिनिधि अपने दायित्व निभा सकें, लोकतंत्र की सेहत के लिए आवश्यक माना जा रहा है।

हालांकि, इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे संवैधानिक अधिकारों की जीत बता रहे हैं, तो वहीं कुछ का मानना है कि गंभीर मामलों में आरोपित नेताओं को विशेष रियायत नहीं मिलनी चाहिए। बावजूद इसके, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि कस्टडी पैरोल कोई स्थायी राहत नहीं है, बल्कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य केवल निर्वाचित प्रतिनिधि को सीमित समय के लिए अपने संसदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने का अवसर देना है।

अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बजट सत्र के दौरान इंजीनियर रशीद किन मुद्दों को संसद में उठाते हैं और उनकी उपस्थिति से सदन की बहसों पर क्या असर पड़ता है। साथ ही, दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित यात्रा खर्च से जुड़ी अपील पर आने वाले फैसले को भी इस पूरे मामले में अहम माना जा रहा है।

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, आईएएस अधिकारी की जमानत रद्द

(जीएनएस)। गुवाहाटी। गुवाहाटी हाईकोर्ट की ईटानगर पीठ ने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी आईएएस अधिकारी तालो पोटोम की जमानत रद्द कर दी है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आरोपी को तत्काल प्रभाव से हिरासत में लिया जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश को कानून के दुरुपयोग और जांच में जल्दबाजी को लेकर एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।

न्यायमूर्ति यारेनजुंगला लोंगकुमेर ने शुक्रवार को जारी अपने विस्तृत आदेश में कहा कि अधीनस्थ अदालत ने नवंबर 2025 में जमानत देते समय न केवल मामले से जुड़े अहम साक्ष्यों की अनदेखी की, बल्कि स्थापित कानूनी सिद्धांतों को भी दरकिनार कर दिया। अदालत ने निचली अदालत के जमानत आदेश को "विकृत" करार देते हुए कहा कि यह फैसला बिना समुचित विचार और संतोषजनक तर्क के पारित किया गया था, जो न्यायिक विवेक के अनुरूप नहीं है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष के वकील ने दलील दी कि आरोपी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तारी के महज सात दिनों के भीतर जमानत दे दी गई थी, जबकि उस समय जांच शुरुआती चरण में थी। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील और गंभीर अपराध में, जहां आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे आरोप लगे हों, जांच एजेंसियों को पर्याप्त समय और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए थी ताकि वे सभी तथ्यों और सबूतों को ठीक से एकत्र कर सकें।

अदालत ने इस तर्क से सहमति जताते हुए कहा कि जमानत देने से पहले यह देखना आवश्यक था कि जांच किस चरण में है और क्या आरोपी के बाहर रहने से साक्ष्यों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की आशंका हो सकती है। न्यायमूर्ति लोंगकुमेर ने टिप्पणी की कि अधीनस्थ अदालत ने इन पहलुओं पर विचार नहीं किया, जो एक गंभीर त्रुटि है।

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत कोई स्वचालित अधिकार नहीं है, खासकर तब जब आरोप गंभीर प्रकृति के हों और जांच प्रारंभिक अवस्था में हो। अदालत ने कहा कि न्यायिक संतुलन बनाए रखने के लिए पीड़ित पक्ष, समाज और जांच प्रक्रिया के हितों को भी समान रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इस मामले में हाईकोर्ट का आदेश ऐसे समय आया है, जब प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर देशभर में बहस तेज है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से यह संदेश जाता है कि पद और रुतबा कानून से ऊपर नहीं है और यदि किसी अधिकारी पर गंभीर आरोप हैं, तो न्यायिक प्रक्रिया में उसके साथ कोई विशेष रियायत नहीं दी जा सकती।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब आरोपी आईएएस अधिकारी तालो पोटोम को हिरासत में लिया जाएगा और आगे की जांच प्रक्रिया को गति मिलने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस फैसले से न केवल इस विशेष मामले की जांच प्रभावित होगी, बल्कि भविष्य में ऐसे मामलों में निचली अदालतों को भी अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत महसूस होगी।

कानूनी जानकारों के अनुसार, हाईकोर्ट का यह फैसला न्यायिक निगरानी की अहम भूमिका को रेखांकित करता है और यह स्पष्ट करता है कि जमानत जैसे संवेदनशील मुद्दों पर जल्दबाजी में लिए गए फैसलों को ऊपरी अदालतें स्वीकार नहीं करेंगी। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे की जांच में क्या नए तथ्य सामने आते हैं और यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है।

प्रजातंत्र को वास्तविक गणतंत्र में बदलने की जरूरत

> भारी संख्या में युवा शक्तियों से सुसज्जित देश अपनी आंकाक्षाओं की पूर्ति के लिए अब किसी भी सीमा को तोड़ने को आतुर है। युवाशक्ति तेजी के साथ नए-नए विषयों पर काम कर रही है, जिसने हर क्षेत्र में एक ऐसी प्रयोगधर्मी और प्रगतिशील पीढ़ी खड़ी की है, जिस पर दुनिया विस्मित है।

आजादी के लगभग 8 दशक पूरे करने के बाद भारतीय गणतंत्र एक ऐसे मुकाम पर है, जहाँ से उसे सिर्फ आगे ही जाना है। अपनी एकता, अखंडता और सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों के साथ पूरी हुई इन 8 दशकों की यात्रा ने पूरी दुनिया के मन में भारत के लिए एक आदर पैदा किया है। यही कारण है कि हमारे भारतवंशी आज दुनिया के हर देश में एक नई निगाह से देखे जा रहे हैं। उनकी प्रतिभा का आदर और मूल्य भी उन्हें मिल रहा है। हमें सोचना होगा कि आखिर हम उस सपने को कैसा पूरा कर सकते हैं जिसे पूरे करने के लिए सिर्फ कुछ साल बचे हैं। यानि 2047 में भारत को महाशक्ति और विश्वगुरु बनाने का सपना। आजादी के लड़ाई के मूल्य आज भले थोड़ा धुंधले दिखते हों या राष्ट्रीय पर्व औपचारिकताओं में लिपटे हुए, लेकिन यह सच है कि देश की युवाशक्ति आज भी अपने राष्ट्र को उसी ज़ज्बे से प्यार करती है, जो सपना हमारे सेनानियों ने देखा था। आजादी की जंग में जिन नौजवानों ने अपना सर्वस्व निछावर किया, वही ललक और प्रेरणा आज भी भारत के उत्थान के लिए नई पीढ़ी में दिखती है। हमारे प्रशासनिक और राजनीतिक तंत्र में भले ही संवेदना घट चली हो, लेकिन आम आदमी आज भी बेहद ईमानदार और नैतिक है। वह सीधे रास्ते चलकर प्रगति की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहता है। यदि ऐसा न होता तो विदेशों में जाकर भारत के युवा सफलताओं के इतिहास न लिख रहे होते। जो विदेशों में गए हैं, उनके सामने यदि अपने देश में ही विकास के समान अवसर उपलब्ध होते तो वे शायद अपनी मातृभूमि को छोड़ने के लिए प्रेरित न होते। बावजूद इसके विदेशों में जाकर भी उन्होंने अपनी प्रतिभा, मेहनत और ईमानदारी से भारत के लिए एक ब्रांड एंबेसेडर का काम किया है। यही कारण है कि साँप, सपेरों और साधुओं के रूप में पहचाने जाने वाले भारत की छवि आज एक ऐसे तेजी से प्रगति करते राष्ट्र के रूप में बनी है, जो तेजी से अपने को एक

महाशक्ति में बदल रहा है। आर्थिक सुधारों की तीव्र गति ने भारत को दुनिया के सामने एक ऐसे चमकीले क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दिया है, जहाँ व्यवसायिक विकास की भारी संभावनाएं देखी जा रही हैं। यह अकारण नहीं है कि तेजी के साथ भारत की तरफ विदेशी राष्ट्र आकर्षित हुए हैं। बाजारवाद के हो-हल्ले के बावजूद आम भारतीय की शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में व्यापक परिवर्तन देखे जा रहे हैं। ये परिवर्तन आज भले ही मध्यवर्ग तक सीमित दिखते हों, इनका लाभ आने वाले समय में नीचे तक पहुँचेगा। भारी संख्या में युवा शक्तियों से सुसज्जित देश अपनी आंकाक्षाओं की पूर्ति के लिए अब किसी भी सीमा को तोड़ने को आतुर है। युवाशक्ति तेजी के साथ नए-नए विषयों पर काम कर रही है, जिसने हर क्षेत्र में एक ऐसी प्रयोगधर्मी और प्रगतिशील पीढ़ी खड़ी की है, जिस पर दुनिया विस्मित है। सूचना प्रौद्योगिकी, फिल्में, कृषि और अनुसंधान से जुड़े क्षेत्रों या विविध प्रदर्शन कलाएँ हर जगह भारतीय प्रतिभाएँ वैश्विक संदर्भ में अपनी जगह बना रही हैं। शायद यही कारण है कि भारत की तरफ देखने का दुनिया का नजरिया पिछले एक दशक में बहुत बदला है। ये चीजें अनायास और अचानक घट गईं हैं, ऐसा भी नहीं है। देश के नेतृत्व के साथ-साथ आम आदमी के अंदर पैदा हुए आत्मविश्वास ने विकास की गति बहुत बढ़ा दी है। भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता की तमाम कहानियों के बीच भी विश्वास के बीज धीरे-धीरे एक वृक्ष का रूप ले रहे हैं। कई स्तरों पर बंटे समाज में भाषा, जाति, धर्म और प्रांतवाद की तमाम दीवारें हैं। कई दीवारें ऐसी भी कि जिन्हें हमने खुद खड़ा किया है और हमारा बुरा सोचने वाली ताकतें उन्हें संबल दे रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर भी जब देश बँटा हुआ नज़र आता है, तो कई बार आम भारतीय का दुख बढ़ जाता है। घुसपैठ की समस्या भी एक ऐसी समस्या है जिससे लगातार नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। किसी तरह भी वोट बैंक बनाने और सत्ता हासिल करने की होड ने तमाम मूल्यों को शीर्षासन करा दिया है। ऐसे में जनता के विश्वास की रक्षा कैसे की जा सकती है? आजादी के इतने साल के बाद लगभग वही सवाल आज भी खड़े हैं, जिनके चलते देश का बँटवारा हुआ और महात्मा गांधी जैसी विभूतियां भी इस बँटवारे को रोक नहीं पाईं। देश के अनेक हिस्सों में चल रहे अतिवादी आंदोलन, चाहे वे किसी नाम से भी चलाए जा रहे हों या किसी भी विचारधारा से प्रेरित हों। सबका उद्देश्य भारत की प्रगति के मार्ग में रोड़े अटकाना ही है। अनेक विकास परियोजनाओं के खिलाफ इनका हस्तक्षेप यह बताता है कि सारा कुछ बेहतर नहीं है। गणतंत्र को सार्थक करने के लिए हमें साधन संपन्नों और हाशिये पर खड़े लोगों को एक तल पर देखना होगा। क्योंकि आजादी तभी सार्थक है, जब वह हिंदुस्तान के हर आदमी को समान विकास के अवसर उपलब्ध कराए। कानून की नजर में हर आदमी समान है, यह बात नारे में नहीं, व्यवहार में भी दिखनी चाहिए।

गणतंत्र के बारे में कहा जाता है कि वह सौ सालों में साकार होता है। भारत ने इस यात्रा की भी काफी यात्रा पूरी कर ली है। बावजूद इसके हमें डा. राममनोहर लोहिया की यह बात ध्यान रखनी होगी कि 'लोकराज लोकलाज से चलता है।' इसी के साथ याद आते हैं पं. दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग, जिन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन देकर भारतीय राजनीति को एक ऐसी दृष्टि दी है, जिसमें आम आदमी के लिए जगह है। यह दर्शन हमें दरिद्रनारायण की सेवा की मार्ग पर प्रशस्त करता है। महात्मा गांधी भी अंतिम व्यक्ति का विचार करते हुए उसके लिए इस तंत्र में जगह बनाने की बात करते हैं। हमें सोचना होगा कि गणतंत्र के इन वर्षों में उस आखिरी आदमी के लिए हम कितनी जगह और कितनी संवेदना बना पाए हैं। प्रगति और विकास के सूचकांक तभी सार्थक हैं, जब वे आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने में समर्थ हों। क्या ऐसा कुछ बताने और कहने के लिए हमारे पास है? यदि नहीं...तो अभी भी समय है भारत को महाशक्ति बनाना है, तो वह हर भारतीय की भागीदारी से ही सच होने वाला सपना है। देश के तमाम वंचित लोगों को छोड़कर हम अपने सपनों को सच नहीं कर सकते। क्या हम इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं।

गणतंत्र दिवस इन तमाम सवालों के जवाब खोजने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आया है। बीते समय में आतंकवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रीयता की तमाम गंभीर चुनौतियों के सामने हमारा तंत्र बहुत बेबस दिखा। बावजूद इसके लोकतंत्र में जनता की आस्था बची और बनी हुयी है। हमारी एकता को तोड़ने और मन को तोड़ने के तमाम प्रयासों के बावजूद आम हिंदुस्तानी अपनी समूची निष्ठा से इस देश को एक देखना चाहता है। यह संकल्प लेना होगा कि हम लोकतंत्र में लोगों के भरोसे को जगा पाएं। उनकी उम्मीदों पर अवसाद की परतें न चढ़ने दें। सपनों में रंग भरने की हिम्मत, ताकत और जोश से भरा हो- आम हिंदुस्तानी तो इसी सपने को सच होते हुए देखना चाहता है। यह संयोग ही है कि नया साल और गणतंत्र दिवस हम एक ही महीने जनवरी में मनाते हैं। जाहिर तौर पर हर नए साल का मतलब कलैंडर का बदलना भर नहीं है वह उत्सव है संकल्प का, अपने गणतंत्र में तेज भरने का। आम आदमी में जो भरोसा टूटता दिखता है उसे जोड़ने का। गणतंत्र को तोड़ने या कमजोर करने में लगी ताकतों के मंसूबों पर पानी फेरने का। जनवरी का महीना इसीलिए बहुत खास है क्योंकि यह महीना देश की अस्मिता को पहली बार झकझोर कर जगाने वाले सन्यासी विवेकानंद की जन्मतिथि(12 जनवरी) का महीना है। जिन्होंने पहली बार भारत के दर्शन को विश्वमंच पर मान्यता ही नहीं दिलायी हमारे दबे-कुचले आत्मविश्वास को जागृत किया। यह महीना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन (23 जनवरी) का जिन्होंने विदेशी सत्ता के दांत खट्टे कर दिए और विदेशी भूमि पर भारतीयों के सम्मान की रक्षा के लिए अपनी सेना खड़ी की। जाहिर तौर पर यह महीना सही संकल्पों और महानायकों की याद का महीना है। इससे हमें प्रेरणा लेने और आगे बढ़ने की जरूरत है। नए साल का सूरज हमें एक नयी रोशनी दे रहा है उसका उजास हमें नई दृष्टि दे रहा है। क्या हम इस रोशनी से सबक लेकर, अपने महानायकों की याद को बचाने और देश को महाशक्ति बनाने के सपने के साथ खड़ा होने का हौसला दिखाएंगें?

संपादकीय

प्रदूषण बनाम टैरिफ

दावोस में हाल ही में संपन्न वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारतीय अर्थव्यवस्था की चर्चा के दौरान यह बात शिद्दत से उठी कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ के मुकाबले प्रदूषण ज्यादा घातक असर दिखा रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और आईएमएफ की पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने इकोनॉमिक फोरम में चर्चा के दौरान कहा कि व्यापार बढ़ाने की कवायद में अकसर व्यापारिक बाधाओं और नियमों की बात की जाती है, लेकिन आर्थिक तरक्की में बाधक प्रदूषण जैसे घटकों की चर्चा कम ही होती है। चर्चा में भारत में प्रदूषण की भयावहता का जिक्र करते हुए कहा गया कि भारत पर ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के मुकाबले प्रदूषण का असर ज्यादा घातक व दूरगामी है। फोरम में साल 2022 में विश्व बैंक के एक अध्ययन का हवाला दिया गया कि भारत में हर साल सत्रह लाख लोगों की मौत प्रदूषण से हो जाती है। ये आंकड़ा भारत में मरने वालों का अट्ठारह फीसदी बैठता है। जो कहीं न कहीं आर्थिक गतिविधियों को बाधित करने के साथ ही बहुमूल्य जीवन भी लीलता है। कमोबेश यह घातकता जीडीपी पर भी असर डालती है। निस्संदेह, प्रदूषण से होने वाली मौतों से केवल एक परिवार ही नहीं, पूरे देश पर प्रभाव पड़ता है। देश की श्रम शक्ति का ह्रास होता है और आर्थिकी पर दूरगामी प्रभाव होते हैं। वहीं आर्थिकी पर चर्चा के दौरान यह मुद्दा भी उठा कि प्रदूषण के चलते निवेशकों के भरोसे पर भी दुष्प्रभाव होता है। इससे निवेशकों का आकर्षण कम होता है। निस्संदेह, निवेशक के मन में भय होता है कि यदि वह इसी प्रदूषित वातावरण में रहता है तो यह उसके लिये यह घातक हो सकता है। इसमें दो राय नहीं कि प्रदूषण की भयावह स्थिति दुनिया में किसी भी देश की छवि को नुकसान जरूर पहुंचाती है। जिससे निवेशक बेहतर विकल्प की तलाश में अन्य देशों का रुख कर सकते हैं। ऐसे में प्रदूषण के संकट को युद्धस्तर पर निपटाने की जरूरत महसूस की जा रही है।

निस्संदेह, भारत में प्रदूषण का संकट एक यथार्थ है। यह भी हकीकत है कि देश के नीति-नियंता प्रदूषण संकट के समाधान को लेकर गंभीर नजर नहीं आते। जब-जब प्रदूषण संकट गहराता है तो आग लगने पर कुआं खोदने की कवायद की जाती है। कोर्ट की फटकार व नियामक एजेंसियों की सख्ती के बाद शासन-प्रशासन हरकत में आता है। लेकिन गीता गोपीनाथ के तर्कों के कुछ अर्धसत्य भी हैं। इसमें दो राय नहीं कि अमेरिका के इशारे पर काम करने वाली वैश्विक एजेंसियां विकासशील देशों को लेकर अपनी सुविधा के हिसाब से प्रतीक-प्रतिमान गढ़ती रही हैं। आईएमएफ जैसी संस्थाओं को अमेरिकी कूटनीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। यहां तक कि इन संस्थाओं में उच्च पदों पर बैठे भारतीय अधिकारी भी अमेरिका के सुरों में गाते नजर आते हैं। सवाल गोपीनाथ के बयान के समय का भी है जब अमेरिका न केवल भारत पर अन्यायपूर्ण टैरिफ लगा रहा है बल्कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते को भी अपनी शर्तों के अनुरूप अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहा है। बहरहाल, इसके बावजूद यह एक हकीकत है कि हमारे देश में प्रदूषण संकट बड़ा है, जिसे देश के नीति-नियंता गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जिसके चलते करोड़ों भारतीयों को अपनी जमा-पूंजी अपने व परिवार के उपचार में खर्च करनी पड़ती है। निस्संदेह, प्रदूषण के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कानूनों को सरल बनाने की भी जरूरत है ताकि उन पर अमल आसानी से हो सके। इसके अलावा लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है कि देश की आबोहवा सुधारने के लिये उन्हें भी कुछ त्याग करने होंगे। उन्हें अपनी विलसिता की जीवन शैली में बदलाव लाकर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधारना होगा। निश्चित रूप से प्रदूषण को आर्थिक चुनौती के रूप में भी देखने की जरूरत है। खासकर जब भारत खुद को वैश्विक आर्थिक और विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिये प्रयासरत है। हमारा मकसद हो कि हमारे शहर स्वच्छ रहें और नागरिकों के लिये जीवन परिस्थितियां स्वास्थ्य के अनुकूल हों।

प्रेरणा

जब समय अपनी चाल चलता है

गुरु सत्येन्द्रनाथ अपने शिष्यों के बीच शांति से बैठे थे। सांझ का समय था, हवा में हल्की ठंडक और वातावरण में एक अजीब-सी स्थिरता थी। गुरुजी का स्वर गंभीर था, लेकिन उसमें करुणा की गर्माहट भी थी। वे कह रहे थे कि जीवन में तीन शक्तियाँ हमेशा एक-दूसरे से उलझी रहती हैं—दिल, दिमाग और किस्मत। दिल इच्छाओं से भरा होता है, वह चाहता है कि जो भी अच्छा लगे, वह तुरंत मिल जाए। दिमाग उन इच्छाओं को पाने के लिए योजनाएँ बनाता है, रास्ते खोजता है, तर्क गढ़ता है और उपाय सुझाता है। लेकिन इन सबके ऊपर एक ऐसी शक्ति है, जिसे मनुष्य चाहकर भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता—वह है किस्मत। अंततः वही घटित होता है, जो समय और भाग्य की धारा में लिखा होता है।

शिष्यों में से अधिकांश गुरुजी की बातों को श्रद्धा से सुन रहे थे, लेकिन सुबोध नामक एक युवक के मन में हलचल थी। वह पढ़ा-लिखा था, मेहनत में विश्वास रखता था और मानता था कि मनुष्य अपने पुरुषार्थ से सब कुछ हासिल कर सकता है। उसे यह स्वीकार करना कठिन लग रहा था कि भाग्य इतना प्रभावशाली हो सकता है कि वह दिल और दिमाग दोनों की योजनाओं को पीछे छोड़ दे। उसने विनम्रता से गुरुजी से कहा कि यदि मनुष्य सही दिशा में प्रयास करे, तो वह अपनी किस्मत भी बदल सकता है। गुरुजी मुस्कराए। उन्होंने सुबोध की आँखों में झाँका और बिना कोई तर्क दिए, उसे अपने साथ चलने को कहा।

वे दोनों पास ही स्थित एक बड़े बगीचे में पहुँचे। बगीचा हरा-भरा था, लेकिन वहाँ सन्नाटा था। कुछ दूरी पर एक जामुन का पेड़ था, जिस पर काले-नीले जामुन लदे हुए थे। उसी पेड़ के नीचे एक बंदर बैठा था। उसकी आँखों में भूख साफ झलक रही थी। वह बार-बार जामुन की ओर देखता, फिर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता। जैसे ही वह चढ़ने लगता, बगीचे का बागबान मोटा डंडा उठाकर उसे डराने लगता। बंदर डरकर नीचे कूद आता। उसने कई बार प्रयास किया, अलग-अलग कोण से चढ़ने की कोशिश की, कभी दाएँ से तो कभी बाएँ से, लेकिन हर बार वही डंडा उसके सामने आ जाता। भूख के कारण उसका धैर्य टूट रहा था, लेकिन हालात उसके अनुकूल नहीं थे।

सुबोध यह दृश्य ध्यान से देख रहा था। उसे लगा कि बंदर का दिल जामुन चाहता है, दिमाग रास्ता खोज रहा है, लेकिन परिस्थितियाँ उसे रोक रही हैं। तभी बगीचे के दूसरे सिरे से एक बुजुर्ग व्यक्ति आते दिखाई दिए। उनके हाथ में केले का एक बड़ा गुच्छा था। वे धीरे-धीरे चलते हुए उसी जामुन के पेड़ के पास आए और कुछ देर रुककर केले का गुच्छा वहीं जमीन पर रख दिया। फिर वे बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। बंदर ने पहले तो डरते-डरते चारों ओर देखा, फिर केले की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने केले देखे, उसकी आँखों में चमक आ गई। उसने बिना किसी डर के केले उठाए, छीलना शुरू किया और आनंद से खाने लगा। कुछ ही क्षणों में उसकी भूख शांत हो गई। जामुन का पेड़ वहीं खड़ा था, लेकिन अब बंदर को उसकी ओर देखने की भी जरूरत नहीं थी।

यह दृश्य देखकर सुबोध के मन में कुछ टूट-सा गया और कुछ जुड़-सा भी गया। गुरु सत्येन्द्रनाथ ने शांति से कहा कि बंदर ने जामुन पाने की पूरी कोशिश की। उसका दिल जामुन चाहता था, दिमाग रास्ता ढूँढ रहा था, लेकिन परिस्थितियाँ उसके विरुद्ध थीं। अंत में जो उसे मिला, वह उसकी योजना का परिणाम नहीं था, बल्कि समय की व्यवस्था थी। यदि वह जामुन पाने में सफल होता, तो शायद केले कभी सामने न आते। लेकिन जब जामुन उसकी किस्मत में नहीं थे, तब केले उसके हिस्से में आए—और वे भी पर्याप्त मात्रा में।

सुबोध चुप था। उसे अपने जीवन की कई घटनाएँ याद आने लगीं। उसने कितनी ही बार किसी लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत की थी, योजनाएँ बनाई थीं, लेकिन परिणाम कुछ और ही निकला था। और कई बार बिना विशेष प्रयास के ऐसे अवसर मिल गए थे, जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसे समझ में आने लगा कि कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, लेकिन फल का निर्धारण समय करता है। दिल और दिमाग मनुष्य के भीतर की शक्तियाँ हैं, पर किस्मत उस व्यापक व्यवस्था का हिस्सा है, जो मनुष्य से कहीं बड़ी है।

गुरुजी ने आगे कहा कि किस्मत को दोष देना या उस पर अंधा विश्वास करना—दोनों ही गलत हैं। सही मार्ग यह है कि मनुष्य पूरे मन से प्रयास करे, लेकिन परिणाम को लेकर अत्यधिक आसक्ति न रखे। जब अपेक्षा कम होती है, तब पीड़ा भी कम होती है और जब मन स्वीकार की अवस्था में होता है, तब जीवन सहज हो जाता है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जो आज नहीं मिला, वह कल किसी और रूप में मिल सकता है। कभी-कभी जो नहीं मिला, वही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान होता है।

सुबोध ने गुरुजी के चरणों में सिर झुका दिया। उसके मन में अब विरोध नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी। उसने स्वीकार कर लिया कि जीवन केवल योजनाओं और इच्छाओं का खेल नहीं है, बल्कि समय के साथ बहने की कला है। जब मनुष्य इस कला को सीख लेता है, तब हर परिस्थिति में उसे कुछ न कुछ सीखने और पाने को मिल ही जाता है। उसी क्षण सुबोध ने अनुभव किया कि समय का फेर समझ में आ जाए, तो जीवन की सबसे बड़ी उलझन अपने आप सुलझने लगती है।

आखिर कबतक जटिल पूर्वाग्रहों से परेशान रहेगा भारत गणतंत्र?

भारत का गणतंत्र पूर्वाग्रहों जैसे जातिवाद, सांप्रदायिकता, भाषा जनित क्षेत्रवाद, वंशवाद, राजनीतिक पक्षपात और सामाजिक असमानताओं से जूझ रहा है, जो संवैधानिक मूल्यों को कमजोर कर रहे हैं। खासकर गणतंत्र दिवस जैसे अवसरों पर ये मुद्दे अकसर उभरकर सामने आ जाते हैं, जहां लोकतंत्र की चुनौतियां स्पष्ट दिखती हैं। इसलिए कतिपय प्रमुख पूर्वाग्रहों पर चर्चा लाजिमी है जो इसे समदर्शी और सर्वसम्मत लोकतंत्र बनने देने की राह के सबसे बड़े रोड़े तब भी थे, आज भी हैं और अगर यही हालात बने रहे तो भविष्य में भी रहेंगे। लिहाजा प्रबुद्धजनों से लेकर आम आदमी के दिलोदिमाग में यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि आखिर कबतक जटिल पूर्वाग्रहों से परेशान रहेगा भारत गणतंत्र? पिछली शताब्दी के अंतिम तीन भागों से लेकर मौजूदा शताब्दी के प्रथम भाग तक यानी पूरे सौ सालों में भारतीय शासन-प्रशासन की जो पूर्वाग्रही गतिविधियां दिखाई-सुनाई पड़ीं, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारतीय गणतंत्र को दलित-आदिवासी-पिछड़े-अल्पसंख्यक-सवर्ण कोटि के अभिजात्य वर्गों के चंगुल से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। खासकर धर्मनिरपेक्षता ने तो एक पाकिस्तान दे देने के बाद कई और पाकिस्तान देने की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। शांतिपूर्ण सनातन भूमि पर ब्रेक के बाद होते रहने वाले सांप्रदायिक दंगे भी इसी बात की चुगली करते प्रतीत होते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया की मुहिम हमारी धर्मनिरपेक्ष सोच को खुली चुनौती देती है, लेकिन प्रशासनिक लाचारी भी जगजाहिर है, जिसे बदले बिना धर्मनिरपेक्ष पूर्वाग्रहों से मुक्ति पाना बिल्कुल कठिन है।

वहीं, भारतीय संविधान से जिन दलितों, पिछड़ों, सवर्णों और अल्पसंख्यकों ने स्थायी लाभ लिए, अब वहीं इसे वंशानुगत बनाये रखने की सियासी तिकड़म रच रहे हैं। यह संवैधानिक लाभ महादलितों, अत्यंत पिछड़े लोगों, गरीब सवर्णों और पसमांदा लोगों तक पहुंचे, इसकी राह में तरह तरह से रोड़े अटकाए जाते हैं। जिस तरह से जातिवादी आरक्षण का दुरूपयोग हो रहा है और एक बार इसका लाभ ले चुके लोग अपने बच्चों के लिए दुबारा लाभ लेने से भी नहीं हिचकिचाते हैं, जिससे जरूरतमंद लोगों तक आरक्षण का लाभ पहुंचना मुश्किल हो रहा है। आरक्षण के जातीय स्वरूप, क्रीमीलेयर मानदंडों में अव्यवहारिक तर्क और एक ही व्यक्ति को बार बार निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण देने या फिर एक ही परिवार को नौकरियों में बार बार आरक्षण का लाभ देते रहने से यह पवित्र सोच भी अब कलुषित हो चुकी है। समाज के अन्य लोगों में इससे सत्ता प्रतिष्ठान के प्रति गहरा रोष देखा जाता है।

सच कहूं तो जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसे पूर्वाग्रह समदर्शिता की राह के रोड़े बनकर भारतीय गणतंत्र की जड़ों को खोखला कर रही हैं, जबकि सर्वसम्मति की जगह बहुमत वाला गणतंत्र अपने ही अल्पमत लोगों के नैसर्गिक हितों पर कुठाराघात करता प्रतीत होता है। आलम यह है कि प्रवासी मजदूरों और छात्रों तक को प्रताड़ित करने में साधन संपन्न वर्ग नहीं हिचकता और भीड़ का न्याय भी जहां तहां सम्पन्न लोगों के खिलाफ दिख जाता है। भारत में ब्रेक के बाद होने वाले जातीय या क्षेत्रीय/भाषाई दंगे इसी बात की तस्दीक करते हैं।

दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मीडिया और राजनीतिक विमर्श में पूर्वाग्रही ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, जो नीतिगत मुद्दों को नजरअंदाज कर भावनात्मक विभाजन पैदा करता है। जहां कांग्रेस व क्षेत्रीय दलों की तुष्टीकरण वाली धर्मनिरपेक्ष राजनीति खतरनाक है, तो आरएसएस-बीजेपी की सेक्युलरिज्म विरोधी विचारधारा से भी लोग सांसत में रहने को अभिशप्त हैं। इसलिए बेहतर होगा कि संविधान के प्रस्तावना से 'समाजवादी' और 'सेक्युलर' शब्द हटाने की पहल की जाए, क्योंकि जाति व धर्म की आड़ में इनका दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे में राजनीतिक विवाद स्वाभाविक बात है। आपने देखा होगा कि गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली के टेबलो को लगातार चौथी बार खारिज करने पर आप ने बीजेपी पर पूर्वाग्रह का आरोप लगाया, जबकि गुजरात-उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को प्राथमिकता मिली। वहीं रक्षा मंत्रालय चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष बताता है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध मानता है। पंजाब जैसे राज्यों के टेबलो अस्वीकृति ने भी विवाद बढ़ाया।

ऐसे में संवैधानिक चुनौतियां भी स्वाभाविक हैं। आपको पता होना चाहिए कि संविधान निर्माता डॉ भीम राव अंबेडकर ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि सामाजिक असमानताओं पर लोकतंत्र की 'टॉप ड्रेसिंग' विफल हो जाएगी, जो आज मतदाता सूची शुद्धिकरण और नागरिकता संशोधन अधिनियम से साकार हो रही है। जहां कार्यपालिका का केंद्रीयकरण विधायिका-न्यायपालिका को कमजोर कर रहा है, वहीं UAPA जैसे कानून असहमति को दबाते हैं, लेकिन आपराधिक मिजाज पर अंकुश लगाते हैं।। कुलमिलाकर तमाम किंतु परन्तु के चलते देश में आर्थिक असमानता और बेरोजगारी जैसे मुद्दे गर्त में या हाशिए पर धकेल दिए गए हैं, जो सार्वजनिक चिंता और लोक दुश्चिंता का सबब बना हुआ है।

देखा जाए तो भारत में राजनीतिक पूर्वाग्रहों के प्रमुख स्रोत पहचान-आधारित राजनीति, मीडिया प्रभाव, सामाजिक ध्रुवीकरण और संस्थागत दबाव आदि हैं। कमोबेश ये तमाम पूर्वाग्रह लोकतंत्र को कमजोर करते हुए विभाजनकारी विमर्श को बढ़ावा देते हैं, जिससे कहीं न कहीं समग्र राष्ट्रहित भ्रमित होता है। जहां पहचान-आधारित राजनीति यानी जाति और धर्म पर आधारित राजनीति पूर्वाग्रहों को गहरा करती है, वहीं दल विशेष इन पहचानों का उपयोग वोट बैंक के लिए करते हैं। वहीं, राम जन्मभूमि आंदोलन और नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे मुद्दों ने हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण बढ़ाया। कुछ लोग आरएसएस-बीजेपी जैसे संगठनों पर सांप्रदायिक पूर्वाग्रह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेसियों और क्षेत्रीय दलों के सांप्रदायिक तुष्टीकरण वाली सोच की निंदा करने में भी गुरेज करते हैं।

एक बात और, मीडिया और सोशल मीडिया यानी मीडिया घरानों पर सरकारी विज्ञापनों, कॉर्पोरेट हितों और राजनीतिक दबाव से पक्षपातपूर्ण कवरेज होता है।

अभियान

त्रिवेणी की गोद में आस्था का महास्नान: प्रयागराज और माघ मेले की अनंत कथा

भारत की आत्मा उसकी आध्यात्मिक परंपराओं में बसती है और उन परंपराओं का सबसे जीवंत रूप तब दिखाई देता है, जब करोड़ों श्रद्धालु एक साथ किसी पवित्र धरा पर एकत्र होते हैं। प्रयागराज में हर वर्ष लगने वाला माघ मेला इसी जीवंत आस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, दर्शन और आत्मिक चेतना का प्रवाह है, जो समय के साथ और भी गहराता गया है। माघ मास की ठंडी सुबहों में संगम की रेती पर जलते अलाव, मंत्रोच्चार की गूंज, साधु-संतों की तपस्वी जीवनशैली और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था—ये सभी मिलकर माघ मेले को एक साधारण उत्सव से कहीं ऊपर, एक दिव्य अनुभूति बना देते हैं।

प्रयागराज का महत्व स्वयं उसके नाम में छिपा है। 'प्रयाग' का अर्थ है यज्ञ, और 'राज' का अर्थ है श्रेष्ठ। अर्थात् यह वह स्थान है, जिसे सभी तीर्थों में सर्वोच्च माना गया है। प्राचीन धर्मग्रंथों में इसे तीर्थराज कहा गया है। मान्यता है कि सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने यहां प्रथम यज्ञ किया था और तभी से यह भूमि देवताओं, ऋषियों और मुनियों की तपोभूमि बन गई। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम इस स्थान को विशिष्ट बनाता है। यह केवल तीन नदियों का मिलन नहीं, बल्कि भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक चेतना का संगम है, जहां स्नान मात्र से ही आत्मा के शुद्ध होने की अनुभूति होती है।

माघ मेला हर वर्ष माघ मास में आयोजित होता है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इस काल में सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर चुका होता है और प्रकृति एक विशेष ऊर्जा से भर जाती है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय साधना, तप और आत्मशुद्धि के लिए सर्वोत्तम माना गया है। यही कारण है कि प्रयागराज में हर वर्ष लाखों साधु-संत, कल्पवासी और श्रद्धालु संगम तट पर एक महीने तक निवास करते हैं। वे कठिन दिनचर्या का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य, संयम और तपस्या के मार्ग पर चलते हैं। यह कल्पवास केवल शरीर को कष्ट देने का साधन नहीं, बल्कि मन और आत्मा को अनुशासित करने की एक गहन साधना है।

माघ मेले की परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर संघर्ष हुआ, तब अमृत कलश से गिरी चार बूंदें पृथ्वी पर चार स्थानों—हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक—में गिरीं। यही चार स्थान कुंभ और अर्धकुंभ जैसे विशाल आयोजनों के केंद्र बने। प्रयागराज को यह विशेष सौभाग्य प्राप्त है कि यहां प्रतिवर्ष माघ मेला आयोजित होता है, जो कुंभ की निरंतर स्मृति और साधना का प्रतीक है। यह मेला बताता है कि अमृत केवल किसी दिव्य द्रव्य में नहीं, बल्कि निरंतर साधना, भक्ति और आस्था में भी छिपा है।

माघ मेले का सबसे प्रमुख अनुष्ठान संगम स्नान है। ठंडे जल में प्रातःकाल डुबकी लगाना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मसंयम और साहस की परीक्षा भी है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस पवित्र स्नान से जन्म-जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। मौनी अमावस्या, पौष पूर्णिमा, बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा जैसे विशेष पर्वों पर संगम तट पर श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। इन दिनों प्रयागराज मानो एक चलती-फिरती आध्यात्मिक नगरी बन जाता है, जहां हर ओर भक्ति, सेवा और त्याग की भावना दिखाई देती है।

माघ मेला सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां विभिन्न अखाड़ों के साधु-संत अपने शिविर लगाते हैं, शास्त्रार्थ होते हैं, प्रवचन दिए जाते हैं और ज्ञान का आदान-प्रदान होता है। यह मेला केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भारतीय दर्शन, योग, आयुर्वेद और जीवन-पद्धति का जीवंत विद्यालय बन जाता है। दूर-दराज़ के गांवों से आए साधारण लोग यहां संतों के सान्निध्य में जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और सरल जीवन जीने की प्रेरणा लेकर लौटते हैं।

आधुनिक समय में भी माघ मेले की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। तेजी से बदलती जीवनशैली, बढ़ते तनाव और भौतिक प्रतिस्पर्धा के बीच माघ मेला मनुष्य को रुककर आत्मचिंतन करने का अवसर देता है। संगम की रेती पर बिताए गए कुछ दिन लोगों को यह याद दिलाते हैं कि जीवन केवल भोग नहीं, बल्कि योग भी है। यही कारण है कि आज शिक्षित युवा, अधिकारी, व्यापारी और विदेशी पर्यटक भी माघ मेले की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वे यहां आकर भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की गहराई को अनुभव करते हैं।

साल 2026 में आयोजित माघ मेला भी इसी परंपरा का भव्य विस्तार है। 03 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक चलने वाले इस मेले में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। प्रशासन द्वारा आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ परंपराओं का सम्मान बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा भी मिले और आध्यात्मिक वातावरण भी अक्षुण्ण रहे। यह मेला न केवल आस्था का पर्व है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि हजारों वर्षों पुरानी परंपराएं आज भी उतनी ही जीवंत और प्रासंगिक हैं।

अंततः माघ मेला यह सिखाता है कि प्रयागराज केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि चेतना का केंद्र है। यहां आकर मनुष्य अपने भीतर झांकता है, अपने कर्मों का मूल्यांकन करता है और आत्मिक शुद्धि की ओर एक कदम बढ़ाता है। यही कारण है कि हर वर्ष, हर पीढ़ी, हर युग में माघ मेला प्रयागराज में ही लगता है—क्योंकि यह स्थान नहीं बदलता, यह अनुभूति है, यह आस्था है, यह अमृत की वह निरंतर बहती धारा है, जो मानव को मोक्ष की ओर ले जाती है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

डिजिटल दुनिया में सेंधमारी, जीमेल-फेसबुक समेत 14.9 करोड़ खातों के यूजरनेम-पासवर्ड लीक

(जीएनएस)। नई दिल्ली। डिजिटल युग में जहां इंटरनेट ने जीवन को सुविधाजनक बना दिया है, वहीं साइबर अपराधों का खतरा भी उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला दुनिया भर के करोड़ों इंटरनेट उपभोक्ताओं को झकझोर देने वाला है। जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, याहू और आउटलुक जैसे बड़े और भरोसेमंद माने जाने वाले प्लेटफॉर्म्स से जुड़े कुल 14.9 करोड़ से अधिक खातों के यूजरनेम और पासवर्ड लीक होने की बात सामने आई है। साइबर सुरक्षा फर्म 'एक्सप्रेसवीपीएन' की रिपोर्ट और शोधकर्ता जेरेमिया फाउलर के अध्ययन ने इस गंभीर खतरे को उजागर किया है, जिसने डिजिटल सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, लीक हुआ डाटा लगभग 96 जीबी का है, जिसमें केवल ईमेल आईडी और पासवर्ड ही नहीं, बल्कि संबंधित अकाउंट्स में सीधे लॉगिन करने के लिंक भी मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि इस डाटा तक पहुंच रखने वाला कोई भी व्यक्ति बिना ज्यादा मेहनत किए यूजर्स के निजी अकाउंट्स में घुसपैठ कर सकता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा प्रभावित जीमेल के यूजर्स हैं, जिनके लगभग 4.8 करोड़ खातों की जानकारी लीक हुई है। इसके अलावा फेसबुक के 1.7 करोड़, इंस्टाग्राम के 65 लाख, नेटफ्लिक्स के 34 लाख, याहू के 40 लाख और आउटलुक के 15 लाख अकाउंट्स के लॉगिन क्रेडेंशियल भी सार्वजनिक हो गए हैं। यह संख्या बताती है कि यह सिर्फ किसी एक प्लेटफॉर्म की चूक नहीं, बल्कि एक व्यापक साइबर संकट है।

इस पूरे मामले में सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि जिस डाटाबेस में यह संवेदनशील जानकारी संग्रहीत थी, वह न तो पासवर्ड से सुरक्षित था और न ही किसी तरह से एन्क्रिप्ट किया गया था। यानी यह डाटाबेस इंटरनेट पर खुला पड़ा था और कोई भी व्यक्ति इसे खोजकर लाखों यूजर्स की निजी जानकारी तक पहुंच बना सकता था। फाउलर के मुताबिक, यह डाटा अलग-अलग देशों और क्षेत्रों से एकत्र किया गया प्रतीत होता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह किसी संगठित साइबर नेटवर्क या बड़े पैमाने पर किए गए डेटा संग्रह का नतीजा हो सकता है।

रिपोर्ट में यह भी आशंका जताई गई है कि लीक हुए डाटा में केवल सोशल मीडिया या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक सीमित जानकारी नहीं है। इसमें बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन भुगतान ऐप्स और यहां तक कि क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स के लॉगिन क्रेडेंशियल भी शामिल हो सकते हैं। यदि ऐसा है, तो इसका दायरा बेहद खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर लोगों की आर्थिक सुरक्षा पर हमला किया जा सकता है। साइबर अपराधी इस जानकारी का इस्तेमाल कर खातों से पैसे निकालने, फर्जी लेनदेन करने या पहचान की चोरी जैसे अपराधों को अंजाम दे सकते हैं।

एक और गंभीर चिंता यह है कि लीक हुए डाटा में कई देशों के '.gov' डोमेन से जुड़े क्रेडेंशियल भी शामिल बताए जा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि सरकारी ईमेल आईडी और लॉगिन डिटेल्स भी इस डाटा लीक का हिस्सा हो सकते हैं। साइबर विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऐसे क्रेडेंशियल गलत हाथों में चले जाते हैं, तो उनका इस्तेमाल सरकारी नेटवर्क में घुसपैठ, संवेदनशील सूचनाओं की चोरी और यहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में जासूसी के लिए भी किया जा सकता है।

फाउलर ने चेतावनी दी है कि इतनी बड़ी संख्या में यूनिक यूजरनेम और पासवर्ड का सार्वजनिक हो जाना लाखों-करोड़ों लोगों के लिए गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा करता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिकतर यूजर्स को इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि उनका डाटा लीक हो चुका है। वे सामान्य रूप से अपने अकाउंट्स का इस्तेमाल करते रहते हैं, जबकि उनके लॉगिन विवरण पहले से ही साइबर अपराधियों के पास मौजूद होते हैं।

डाटा लीक होने के बाद इसके प्रभाव कई स्तरों पर सामने आ सकते हैं। अपराधी यूजर्स की पहचान का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके नाम से धोखाधड़ी कर सकते हैं। फर्जी लेकिन असली जैसे दिखने वाले ईमेल, मैसेज या कॉल के जरिए लोगों को ठगा जा सकता है, क्योंकि हैकर्स के पास उनकी सही व्यक्तिगत जानकारी होती है। इसके अलावा, आमतौर पर लोग अलग-अलग वेबसाइट्स और ऐप्स पर एक ही या मिलता-जुलता पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में यदि एक अकाउंट का पासवर्ड लीक हो जाए, तो हैकर्स उसी पासवर्ड से बैंक, ईमेल, सोशल मीडिया और अन्य जरूरी अकाउंट्स तक भी पहुंच बना सकते हैं।

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना एक बार फिर यह साबित करती है कि डिजिटल दुनिया में सतर्कता बेहद जरूरी है। मजबूत और अलग-अलग पासवर्ड का इस्तेमाल, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को सक्रिय रखना, संदिग्ध ईमेल या लिंक से दूरी बनाना और समय-समय पर पासवर्ड बदलना अब केवल सलाह नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन चुका है। इसके साथ ही, कंपनियों और प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वे यूजर्स के डाटा की सुरक्षा के लिए मजबूत तकनीकी उपाय अपनाएं।

कुल मिलाकर, 14.9 करोड़ खातों का यह डाटा लीक डिजिटल युग की सबसे बड़ी चेतावनियों में से एक है। यह न केवल आम यूजर्स को, बल्कि सरकारों, संस्थानों और टेक कंपनियों को भी यह सोचने पर मजबूर करता है कि साइबर सुरक्षा को लेकर अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं बची है। डिजिटल सुविधा के साथ-साथ डिजिटल सतर्कता ही आने वाले समय में सबसे बड़ा सुरक्षा कवच साबित हो सकता है।

महाराष्ट्र की नगर राजनीति में शरद पवार का निर्णायक दांव, सांगली और अकोला में भाजपा बहुमत से दूर

(जीएनएस)। सांगली और अकोला के नगर निगम चुनाव नतीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि केवल सबसे बड़ी पार्टी बन जाना सत्ता की गारंटी नहीं होता। इन दोनों नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने के बावजूद बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी है। इस स्थिति ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) को अप्रत्याशित रूप से किंगमेकर की भूमिका में ला खड़ा किया है। महज तीन-तीन पार्षदों के साथ एनसीपी (एसपी) अब सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखती नजर आ रही है और सभी दलों की निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं।

सांगली-मिरज-कुपवाड़ नगर निगम के 78 सदस्यीय सदन में भाजपा को 39 सीटें मिली हैं, जबकि बहुमत के लिए 40 का आंकड़ा जरूरी है। एक सीट की कमी ने भाजपा की जीत को अधूरा बना दिया है। कांग्रेस ने 18 सीटें जीतकर खुद को मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित किया है, वहीं अजित पवार गुट की एनसीपी को 16 सीटें मिली हैं। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना महज दो सीटों पर सिमट गई है, जबकि शरद पवार गुट की एनसीपी तीन सीटों के साथ संतुलन की धुरी बन गई है। राजनीतिक अंकगणित के इस खेल में भाजपा को या तो छोटे दलों का समर्थन जुटाना होगा या फिर निर्दलीयों और अन्य घटकों के सहारे बहुमत तक पहुंचना होगा, लेकिन निर्णायक स्थिति में खड़ी एनसीपी (एसपी) के बिना तस्वीर पूरी होती नहीं दिख रही।

अकोला नगर निगम का हाल भी कुछ ऐसा ही है। 80 सदस्यीय सदन में बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत है, लेकिन भाजपा 38 सीटों पर ही सिमट गई है। कांग्रेस ने यहां 21 सीटें जीतकर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) को छह सीटें मिली हैं, जबकि एनसीपी (एसपी) के खाते में यहां भी तीन सीटें आई हैं। अजित पवार गुट की एनसीपी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को एक-एक सीट मिली है। इसके अलावा एआईएमआईएम, वंचित बहुजन आघाड़ी और निर्दलीयों समेत अन्य दलों के कुल दस पार्षद भी समीकरण को और जटिल बना रहे हैं। ऐसे में अकोला में भी एनसीपी (एसपी) की भूमिका निर्णायक हो गई है, क्योंकि बिना उसके समर्थन के कोई भी दल स्पष्ट बहुमत का दावा नहीं कर पा रहा।

इन नतीजों के बाद सांगली और अकोला दोनों जगह सत्ता गठन को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा के लिए यह चुनौती है कि वह बहुमत जुटाने में सफल हो या फिर विपक्ष में बैठने की रणनीति तैयार करे। इसी बीच यह चर्चाएं भी सामने आ रही हैं कि एनसीपी (एसपी) के पार्षदों से भाजपा संपर्क में है। हालांकि, सांगली में एनसीपी (एसपी) के पार्षद अभिजीत कोली ने साफ किया है कि उनकी पार्टी महाविकास आघाड़ी के घटक के तौर पर जनता के बीच गई थी और सत्ता में हो या विपक्ष में, उनका प्राथमिक लक्ष्य जनहित और विकास रहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा और किसी भी कदम से पहले व्यापक विचार-विमर्श होगा।

अकोला को लेकर एनसीपी (एसपी) के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे का बयान भी राजनीतिक संकेतों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर सभी दलों के साथ बातचीत चल रही है ताकि ऐसा गठबंधन बनाया जा सके जो विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता दे। उनका कहना है कि नगर निगम जैसे स्थानीय निकायों में गठबंधन केवल दलों और उनके चुनाव चिह्नों के आधार पर नहीं, बल्कि शहर की जरूरतों और जनता के हितों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। इस बयान को राजनीतिक गलियारों में एक लचीले रुख के तौर पर देखा जा रहा है, जो एनसीपी (एसपी) को दोनों ही तरफ बातचीत की गुंजाइश देता है।

इन दोनों नगर निगमों के नतीजों ने शरद पवार की राजनीतिक प्रासंगिकता को एक बार फिर रेखांकित कर दिया है। राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में लंबे अनुभव के बाद अब नगर स्तर पर भी उनका गुट निर्णायक भूमिका में नजर आ रहा है। सीमित संख्या में सीटें होने के बावजूद सत्ता के समीकरण तय करने की क्षमता ने यह साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में संख्या से ज्यादा रणनीति मायने रखती है। भाजपा के लिए यह एक चेतावनी भी है कि मजबूत संगठन और ज्यादा सीटों के बावजूद यदि सहयोगी समीकरण साधे नहीं गए, तो सत्ता हाथ से फिसल सकती है।

कुल मिलाकर सांगली और अकोला में उभरी यह स्थिति आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की नगर राजनीति की दिशा तय करेगी। क्या भाजपा समर्थन जुटाकर सत्ता बनाएगी या फिर एनसीपी (एसपी) की भूमिका किसी वैकल्पिक गठबंधन को जन्म देगी, यह आने वाले राजनीतिक संवाद और निर्णयों पर निर्भर करेगा। फिलहाल इतना तय है कि इन दोनों शहरों में सत्ता की चाबी शरद पवार गुट के हाथ में है और पूरा राजनीतिक परिदृश्य उसी के इर्द-गिर्द घूम रहा है।

शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंदजी के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ AAP का प्रचंड विरोध

- मणिनगर रेलवे स्टेशन पर AAP अहमदाबाद शहर संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन
- शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार कर भाजपा ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई : AAP का आरोप
- शंकराचार्य के अपमान के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने वाले AAP नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी
- शंकराचार्य का अपमान करने वाली भाजपा का सनातन से कोई लेना-देना नहीं : विजय पटेल AAP
- भाजपा राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि कॉर्पोरेट कंपनी है, जो धर्म का उपयोग करती है : विजय पटेल AAP
- साधु-संतों के अपमान के लिए भाजपा माफी मांगे : विजय पटेल AAP

(जीएनएस)। अहमदाबाद/गुजरात। आम आदमी पार्टी अहमदाबाद शहर समिति द्वारा प्रयागराज में जगद्गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंदजी के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में अहमदाबाद शहर अध्यक्ष विजय पटेल, मालधारी सेल प्रदेश अध्यक्ष गुजरात किरण देसाई, ASAP मध्य जोन अध्यक्ष यात्रिक पटेल, ASAP अहमदाबाद शहर अध्यक्ष तीर्थ श्रीमाली, महिला शहर अध्यक्ष सिद्धिबेन भावसार, अहमदाबाद शहर उपाध्यक्ष अल्पेश सोलंकी, अहमदाबाद शहर उपाध्यक्ष दिनेश टांक, अहमदाबाद शहर मंत्री मुकेशभाई, असारवा विधानसभा प्रभारी जगदीश वणजारा, युवा मंत्री अहमदाबाद शहर कश्यप पटेल, थलतेज वार्ड अध्यक्ष चिरागभाई देसाई सहित स्थानीय पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। इस कार्यक्रम में भाजपा सरकार ने एक बार फिर पुलिस का दुरुपयोग कर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की थी। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के अहमदाबाद शहर अध्यक्ष विजय पटेल ने कहा कि भाजपा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक कॉर्पोरेट कंपनी है, जो जरूरत के अनुसार धर्म और साधु-संतों का उपयोग कर सत्ता पर बैठी है, लेकिन वास्तव में भाजपा का सनातन धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंदजी के साथ भाजपा प्रशासन ने जिस तरह का व्यवहार किया है वह अत्यंत निंदनीय है,

उनके शिष्यों के साथ भी जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, उसे देखकर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। आज भाजपा को सत्ता का इतना अहंकार हो गया है कि हिंदू परंपरा में सर्वोच्च माने जाने वाले शंकराचार्य से भाजपा, शंकराचार्य होने का प्रमाणपत्र मांगती है, जो अत्यंत निंदनीय है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंदजी के साथ हुए इस व्यवहार के लिए भाजपा माफी मांगे, इसी मांग के साथ आज आम आदमी पार्टी अहमदाबाद शहर संगठन द्वारा मणिनगर रेलवे स्टेशन पर प्रचंड विरोध प्रदर्शन किया गया था।

गुजरात तथा दमण एवं दीव नेवल एरिया के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियल एडमिरल ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात तथा दमण एवं दीव नेवल एरिया के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल श्रीतनु गुरु ने शनिवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की।

1995 में भारतीय नौसेना में जुड़े श्रीतनु गुरु नवंबर-2025 से गुजरात तथा दमण एवं दीव नेवल एरिया के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के रूप में नियुक्त हुए हैं।

इस मुलाकात के अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार उपस्थित रहे।

बसंत पंचमी पर सूरत में सामाजिक समरसता का उत्सव, अग्रसेन भवन में 11 जोड़ों ने थामा जीवनभर का साथ

(जीएनएस)। सूरत। बसंत पंचमी के पावन और शुभ अवसर पर सूरत में सामाजिक सौहार्द, परंपरा और सेवा भावना का अनुपम दृश्य देखने को मिला, जब 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह पूरे धार्मिक उल्लास और पारंपरिक गरिमा के साथ संपन्न हुआ। परम पंडित गणेश नारायण बावलिया बाबा ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित इस सामूहिक विवाह का आयोजन श्री श्याम प्रचार मंडल महिला इकाई एवं अग्रमिलन महिला इकाई के संयुक्त प्रयास से किया गया। सिटीलाइट क्षेत्र स्थित अग्रसेन भवन के पंचवटी हॉल में आयोजित इस समारोह में मंगल गीतों की गूंज, वैदिक मंत्रोच्चार और नवदंपतियों के चेहरे पर झलकती खुशी ने पूरे वातावरण को भावविभोर कर दिया।

बसंत पंचमी को ज्ञान, संस्कार और शुभारंभ का पर्व माना जाता है और इसी भाव के अनुरूप इस दिन 11 जोड़ों ने नए जीवन की शुरुआत की। विवाह स्थल को पारंपरिक सजावट से सुसज्जित किया गया था, जहां पीले रंग की थीम, पुष्प सज्जा और धार्मिक प्रतीकों ने बसंत पंचमी के उल्लास को और भी जीवंत बना दिया। सुबह से ही विवाह स्थल पर चहल-पहल शुरू हो गई थी। वैवाहिक रस्मों के दौरान ढोल-नगाड़ों और मंगल गीतों की मधुर ध्वनि ने आयोजन को उत्सव का रूप दे दिया।

संस्था के संरक्षक पूरणमल अग्रवाल ने बताया कि सामूहिक विवाह में शामिल सभी 11 जोड़े सूरत और उसके आसपास के क्षेत्रों से थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में समानता, सहयोग और आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं। सामूहिक विवाह न केवल आर्थिक रूप से जरूरतमंद परिवारों को सहारा देता है, बल्कि समाज में सादगी और संस्कारों के महत्व को भी रेखांकित करता है। उन्होंने इस आयोजन को सामाजिक दायित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

संस्था की अध्यक्षा शालू खदरिया ने जानकारी दी कि नवयुगल जोड़ों और उनके परिजनों के लिए सगाई से लेकर विदाई तक की संपूर्ण व्यवस्थाएं संस्था द्वारा की गईं।

श्री कमलनयन बजाज की 111 वीं जयंती पर उनके जीवन और विरासत को समर्पित लघु फिल्म का लोकार्पण

श्री शिशिर बजाज और समस्त बजाज समूह परिवार ने अर्पित की श्रद्धांजलि

(जीएनएस)। मुंबई, 23 जनवरी। भारत के प्रख्यात उद्योगपति और स्वाधीनता सेनानी श्री कमलनयन बजाज की 111वीं जयंती के अवसर पर उनकी गौरवशाली जीवन यात्रा को समर्पित विशेष लघु फिल्म का लोकार्पण उनके सुपुत्र और बजाज फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री शिशिर बजाज द्वारा शुक्रवार, 23 जनवरी, 2026 को किया गया।

बजाज समूह परिवार द्वारा निर्मित और यू-ट्यूब पर उपलब्ध यह विशेष लघु फिल्म श्री कमलनयन बजाज के महान व्यक्तित्व और उनके असाधारण जीवन एवं युग को जीवंत करती है, जिन्होंने बजाज समूह की सच्ची उद्यमशील नींव रखी और भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह स्मृतिजनक फिल्म श्री कमलनयन बजाज की उस यात्रा को दर्शाती है, जिसमें वे महात्मा गांधी से प्रेरित एक युवा स्वतंत्रता सेनानी से एक दूरदर्शी उद्योगपति और राष्ट्रनिर्माता बने। वे मानते थे कि व्यवसाय केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक पुनीत देशभक्ति कर्तव्य है। 23 जनवरी, 1915 को जमनालाल बजाज और जानकीदेवी बजाज के घर जन्मे कमलनयन बजाज तीन महान व्यक्तित्वों के नैतिक प्रभाव में पले-बढ़े—अपने पिता जमनालाल बजाज, अपने मार्गदर्शक महात्मा गांधी और अपने गुरु आचार्य विनोबा भावे। जीवन में प्रवेश करते समय ही उनके मूल्य स्पष्ट थे। मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने दांडी मार्च में भाग लिया और स्वदेशी व खादी आंदोलनों के प्रारंभिक समर्थक बने। उस दौर में, जब आर्थिक सशक्तिकरण स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आवश्यक था, वे मानते थे कि उद्देश्य पद या सत्ता से पहले आना चाहिए और उद्यम का लक्ष्य राष्ट्रीय हित की सेवा होना चाहिए। लघु फिल्म यह दर्शाती है कि कैसे कमलनयन बजाज ने सचेत रूप से ऐसे उद्योगों की स्थापना की, जिन्होंने भारत की आयात पर निर्भरता को कम किया और "आत्मनिर्भर भारत" की परिकल्पना को उस समय साकार किया, जब यह शब्द प्रचलन में भी नहीं आया था। अभिलेखीय दृश्यों में उन्हें उत्तर प्रदेश की गोला चीनी मिल का बार-बार दौरा करते हुए दिखाया गया है, जिसे उनके पिता ने चीनी आयात को रोकने के लिए स्थापित किया था। इन दृश्यों में उनका परिवार और उनके छोटे पुत्र शिशिर भी दिखाई देते हैं, जिन्होंने आगे चलकर बजाज हिन्दुस्थान शुगर के बड़े विस्तार का नेतृत्व किया। फिल्म यह भी दर्शाती है कि कैसे उन्होंने उस समय वैश्विक सहयोग स्थापित किये, जब भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी कमजोर थी। ऐसा ही एक सहयोग बजाज इलेक्ट्रिकल्स के लिए वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पनी फिलिप्स के साथ था और दूसरा इतालवी स्कूटर निर्माता पियाजियो की वेस्पा के साथ, जिससे बजाज का ऑटोमोबाइल व्यवसाय शुरू हुआ। इन अग्रणी साझेदारियों ने कमलनयन बजाज को बजाज समूह का वास्तविक उद्यमी सिद्ध किया, जिन्होंने मूल्य-आधारित विरासत को एक वैश्विक स्तर पर सम्मानित औद्योगिक समूह में रूपांतरित किया। व्यवसाय से परे, कमलनयन बजाज 15 वर्षों तक महाराष्ट्र के वर्धा क्षेत्र से संसद सदस्य रहे और ग्रामीण समुदायों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए स्वयं को समर्पित किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत कार्यों और सांस्कृतिक संस्थानों को सुदृढ़ करने में निरंतर योगदान दिया। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण में भी एक शांत किंतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से रियासतों के एकीकरण के दौरान सरदार वल्लभभाई पटेल की सहायता की। इस योगदान का उल्लेख वी.पी. मेनन ने अपनी पुस्तक में किया है। वीडियो में वर्धा स्थित बजाजवाड़ी को भी पुनः दर्शाया गया है, जो सौहार्द, संवाद और राष्ट्रीय सेवा का प्रतीक बन गई थी। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, सरोजिनी नायडू, मोरारजी देसाई, खान अब्दुल गफ्फार खान और यहां तक कि नेपाल के राजा-रानी जैसे अनेक नेता आये। सेवाग्राम आश्रम में गांधीजी से मिलने के लिए ये यात्राएँ इतनी नियमित थीं कि महात्मा गांधी ने बजाजवाड़ी को "राष्ट्रीय अतिथि गृह" कहा था। लोकार्पण के इस महत्वपूर्ण अवसर पर बजाज फाउंडेशन के चेयरमैन श्री शिशिर बजाज ने कहा कि मेरे पिता का मानना था कि जो हम बनाते हैं वह टिकाऊ होना चाहिये और जो टिकाऊ हो, उसे समाज की सेवा करनी चाहिये। उनके लिए उद्योग, सार्वजनिक सेवा और सामाजिक संस्थान—तीनों राष्ट्र निर्माण के अविभाज्य स्तम्भ थे। उन्होंने कहा कि यह श्रद्धांजलि हमारी ओर से आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाने का एक विनम्र प्रयास है कि मूल्य- आधारित उद्यमिता व्यवसाय और समाज दोनों को रूपांतरित कर सकती है। फिल्म कमलनयन बजाज के व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रकाश डालती है, जिसमें 19 वर्ष की आयु में सावित्री देवी से उनका विवाह, उनके सभी प्रयासों में उनका अटूट समर्थन और उनके बच्चों द्वारा उनके मूल्यों और दृष्टि को आत्मसात करना मुख्य रूप से शामिल है। उनके बड़े पुत्र राहुल बजाज और छोटे पुत्र शिशिर बजाज ने आगे चलकर उनके द्वारा स्थापित व्यवसायों का उल्लेखनीय विस्तार किया। वर्तमान में यह गरिमापूर्ण विरासत श्री शिशिर बजाज और उनके पुत्रों के माध्यम से आगे बढ़ रही है। उनके बड़े पुत्र कुशाग्र बजाज, जो वर्तमान में उनके व्यवसाय पक्ष के चेयरमैन हैं, और छोटे पुत्र अपूर्व बजाज। वे कमलनयन बजाज के उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें उद्यम को सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ा गया है। बजाज समूह के औद्योगिक विस्तार से लेकर वर्धा, सीकर और ललितपुर में ग्रामीण विकास पहलों को गहराई देने तक, परिवार सामाजिक- आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध बना हुआ है। डिजिटल और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जारी यह श्रद्धांजलि फिल्म कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर अभिलेखीय तस्वीरों को पुनर्स्थापित, सजीव और कथानक रूप में प्रस्तुत करती है, जिससे इतिहास युवा पीढ़ी के लिए सुलभ बनता है और कमलनयन बजाज के जीवन की गरिमा और गम्भीरता भी बनी रहती है। इस सुरुचिपूर्ण फिल्म का इन हाउस प्रोडक्शन, पटकथा लेखन एवं वॉयस ओवर बजाज समूह की कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन्स महाप्रबंधक सुश्री सुरुचि महतपुरकर कोरे द्वारा सुनिश्चित किया गया है। जब राष्ट्र श्री कमलनयन बजाज को उनकी 111वीं जयंती पर स्मरण कर रहा है, तब बजाज परिवार की यह सृजनात्मक श्रद्धांजलि एक कालातीत संदेश दोहराती है कि सच्ची उद्यमिता केवल विस्तार से नहीं, बल्कि राष्ट्र की सेवा और मूल्यों की संरक्षा से परिभाषित होती है।

बसंत पंचमी पर सेवा और संस्कार का संगम, बैटर टुमारो फाउंडेशन ने 400 से अधिक बच्चों को कराया पौष्टिक भोजन

(जीएनएस)। सूरत। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर बैटर टुमारो फाउंडेशन की ओर से मानव सेवा और सामाजिक समर्पण का प्रेरक उदाहरण देखने को मिला, जब संस्था द्वारा संचालित 'नर सेवा नारायण सेवा' पौष्टिक आहार अभियान के तहत सैकड़ों जरूरतमंद बच्चों के लिए भोजन सेवा का आयोजन किया गया। यह सेवा शुक्रवार शाम उधना–मगदल्ला रोड स्थित राधाकृष्ण मंदिर परिसर में संपन्न हुई, जहां श्रद्धा, उत्साह और करुणा का वातावरण पूरे आयोजन के दौरान बना रहा। फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस विशेष आहार सेवा का अवसर बसंत पंचमी के साथ-साथ बाबोसा के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया गया। धार्मिक आस्था और सामाजिक दायित्व के इस संगम ने कार्यक्रम को और अधिक भावनात्मक तथा प्रेरणादायी बना दिया। शाम छह बजे से शुरू हुई इस सेवा में 400 से अधिक बच्चों ने पौष्टिक और संतुलित भोजन ग्रहण किया। भोजन पाने वाले बच्चों के चेहरों पर संतोष और मुस्कान साफ झलक रही थी, जो इस पूरे आयोजन की सार्थकता को दर्शा रही थी। बैटर टुमारो फाउंडेशन की ओर से बताया गया कि संस्था लंबे समय से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए निरंतर कार्य कर रही है। फाउंडेशन का उद्देश्य केवल भोजन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसी सोच के तहत संस्था स्लम क्षेत्रों, वृद्धाश्रमों, भिक्षु गृहों, गौशालाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बस्तियों में नियमित रूप से पौष्टिक आहार सेवा उपलब्ध कराती आ रही है। बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित यह सेवा उसी निरंतर अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी रही।

कार्यक्रम के दौरान बाबोसा का जन्मोत्सव भी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। धार्मिक अनुष्ठानों और सेवा कार्य के संयोजन ने उपस्थित लोगों के मन में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को और गहरा किया।

पश्चिम रेलवे

OHE कार्य

सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (सबर्बन), वेस्टर्न रेलवे, मुंबई सेंट्रल, मुंबई 400 008, ई-टेंडर नंबर: WR MMCTOESUB (ESOT)/18/2025, तारीख: 21.01.2026 आमंत्रित करते हैं। काम का नाम: अंधेरी-दादर - UPTH और DNTH लाइन के अनरेगुलेटेड OHE को रेगुलेटेड O H E में बदलना। काम की अनुमानित लागत: RS. 9,56,02,478/-. बिड सिक्योरिटी: Rs. 6,28,000/-. जमा करने की तारीख और समय: ता.20.02.2026 के 15: 00 बजे तक निर्धारित तरीके से। खोलने की तारीख और समय: ता.20.02.2026 को 15:30 बजे। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं। 1042

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

पुलों पर साइड पाथवे का प्रावधान

डेप्युटी CE(ब्रिज-लाइन)-दादर, वेस्टर्न रेलवे ई-टेंडर नोटिस नंबर:DYCE-BR-DDR-2026-02, तारीख: 21.01.2026 जारी करता है। काम का नाम:मुंबई डिवीजन के SSE(ब्रिज) वलसाड के अधिकार क्षेत्र में सफाले-सूरत सेक्शन में ब्रिज नंबर 325DN, 332DN, 440 थर्ड लाइन, 440 शु. नेक, 442 थर्ड लाइन और 445 थर्ड लाइन पर साइड पाथवे का प्रावधान। काम की अनुमानित लागत: ₹ 1,75,35,319.43. EMD: ₹ 2,37,700/-. ई-टेंडर जमा करने और ई-टेंडर खोलने की तारीख और समय: ऑनलाइन टेंडर ता.17.02.2026 को 15.00 बजे से पहले जमा करना है, और उसी तारीख - 17.02.2025 को 15.30 बजे खोला जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं। 1046

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

सामग्री प्रबंधन विभाग

विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति

ई-प्रोक्योरमेंट टेंडर सूचना संख्या S/05/2026 दिनांक 23.01.2026

क्र.नं.	आइटम का संक्षिप्त विवरण	मात्रा	टि.ओ.डी
40	एक्सेसरीज़ और CAMC के साथ डायनामिक व्हील बैलेंसिंग मशीन	2 नंग 1 सेट	24-फरवरी-26
41	PU लाइनिंग का सेट	4800 सेट	25-फरवरी-26
42	RDSO DRG. संख्या T: 4865 के अनुसार 1 में 8.5, 60kg टर्न-आउट के लिए 6 mm मोटे नायलॉन कॉर्ड GRSP की आपूर्ति के लिए एक वर्ष का रनिंग कॉन्ट्रैक्ट	1466 सेट	24-फरवरी-26
43	ओवरहॉलिंग किट	854 सेट	24-फरवरी-26
44	टेपर्ड स्टेशनरी प्लेट	2592 नंग	23-फरवरी-26
45	पिनियन के साथ ट्रैक्शन मोटर कम्प्लीट	2 नंग	23-फरवरी-26
46	रूफ अर्थिंग स्विच (HOM)	95 नंग	23-फरवरी-26
47	RDSO ड्राइंग संख्या T-10232 और T-10235 के अनुसार HVN-66 इंसुलेटिंग कट लाइनर की आपूर्ति के लिए एक वर्ष का रनिंग कॉन्ट्रैक्ट	598700 नंग	23-फरवरी-26
48	पश्चिमी रेलवे के विभिन्न डिवीजनों में काम करने वाली लोरम मेक RGM मशीन के स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति के लिए एक वर्ष की अवधि यानी 2026-27 के लिए दर अनुबंध	1 सेट	20-फरवरी-26
49	RDSO, DRG. के अनुसार 60kg रेल के साथ चौड़े बेस स्लीपर पर ERC J-टाइप के साथ उपयोग के लिए HVN कट लाइनर (ग्लू वाले जोड़ों के लिए) की आपूर्ति के लिए एक वर्ष का रनिंग कॉन्ट्रैक्ट नं. T-10228 और 10225	432000 नंग	20-फरवरी-26
50	MK-50 के लिए मूवेबल प्लेट	2592 नंग	18-फरवरी-26

विस्तृत नोटिस EMD, खरीद प्रतिबंध और विस्तृत टेंडर शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट www.ireps.gov.in और wr.indianrailways.gov.in पर जाएं। 1051

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फोलो करें: X.com/WesternRly

नांदेड़ में 'हिंद की चादर' शहीदी समागम से गूंजा त्याग और बलिदान का संदेश, गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व पर उमड़ा आस्था का सागर

(जीएनएस)। नांदेड़ की पावन धरती इन दिनों इतिहास, श्रद्धा और बलिदान की स्मृतियों से जीवंत हो उठी है। मानवता, धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले 'हिंद की चादर' श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के अवसर पर यहां आयोजित दो दिवसीय भव्य समागम ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया है। तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब से शुरू हुए इस ऐतिहासिक आयोजन में देशभर से लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर ओर गुरु की महिमा, गुरबाणी की गूंज और सेवा-समर्पण का भाव दिखाई दे रहा है।

शनिवार सुबह समागम का शुभारंभ भव्य नगर कीर्तन से हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब की पावन स्थापना के साथ ही पूरा नांदेड़ शहर श्रद्धा में डूब गया। पालकी साहब को पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जो गुरु परंपरा के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक बना। नगर कीर्तन के दौरान संगत ने शबद-कीर्तन गाए, अरदास की और गुरबाणी के पवित्र पाठ से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। सड़कों के दोनों ओर खड़े श्रद्धालु हाथ जोड़कर शीश नवाते नजर आए, मानो इतिहास स्वयं वर्तमान से संवाद कर रहा हो।

इस शहीदी समागम की विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रशासन और आयोजन समिति को देश के कोने-कोने से करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इतनी बड़ी संख्या में आने वाली संगत की सुविधा के लिए 52 एकड़ के विशाल क्षेत्र में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहां ठहरने, विशाल लंगर व्यवस्था, पीने के पानी, स्वच्छता, चिकित्सा सेवाओं और सुरक्षा के पुख्ता

प्रबंध किए गए हैं। हजारों सेवादार दिन-रात सेवा में जुटे हुए हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की असुविधा न हो। लंगर में जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर सभी को समान भाव से भोजन कराया जा रहा है, जो सिख परंपरा की मूल भावना को दर्शाता है।

आयोजन समिति के अनुसार, यह समागम केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि गुरु तेग बहादुर जी के उस महान बलिदान को स्मरण करने का अवसर है, जिसने भारतीय समाज में धार्मिक स्वतंत्रता की नींव को और मजबूत किया। इतिहास गवाह है कि जबरन धर्म परिवर्तन के विरोध में गुरु तेग बहादुर जी ने अपने प्राणों का बलिदान देकर यह सिद्ध किया कि धर्म केवल पूजा-पद्धति नहीं, बल्कि मानव गरिमा और स्वतंत्रता का आधार है। उनका बलिदान आज भी देश को सहिष्णुता, आपसी सम्मान और मानवता का मार्ग दिखाता है।

इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन, राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण और शहीदी समागम राज्य समिति के समन्वयक रमेश्वर नायक सहित अनेक वरिष्ठ नेता और सामाजिक हस्तियां मौजूद रहीं। सभी ने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को नमन करते हुए इसे पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। समागम के दौरान दो दिनों तक कीर्तन दरबार, ढाडी जत्थों की वीर रस से ओतप्रोत प्रस्तुतियां और गुरुओं के जीवन प्रसंगों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो संगत को भाव-विभोर कर रहे हैं।

समागम को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि त्याग और बलिदान की भावना पंजाबियों के खून में रची-बसी है और यह विरासत उन्हें अपने गुरुओं से मिली है। उन्होंने कहा कि चाहे देश के किसी भी कोने में चुनौती आए, पंजाबियों ने हमेशा सबसे आगे बढ़कर देश की रक्षा की है। जब भी दुश्मन की ओर से गोली चली है, पंजाब के बेटे-बेटियां सबसे पहले उसका सामना करने खड़े हुए हैं, चाहे वह कारगिल हो, जैसलमेर हो, गंगानगर हो या बीकानेर। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर खड़ा होना ही सच्ची भक्ति है।

इस ऐतिहासिक आयोजन को और भी विशेष बनाने के लिए रविवार को देश के कई बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के कार्यक्रम में शामिल होने की पुष्टि की गई है। जिला सूचना कार्यालय के अनुसार, अमित शाह रविवार दोपहर करीब दो बजे नांदेड़ पहुंचेंगे और सबसे पहले तख्त सचखंड गुरुद्वारा श्री हजूर साहिब में मत्था टेकेंगे। इसके बाद वे मोदी ग्राउंड में आयोजित 'हिंद की चादर' शहीदी समागम में शामिल होंगे और संगत को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के बाद वे शाम करीब 4:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं पवन कल्याण अपराह्न 1:30 बजे तख्त सचखंड गुरुद्वारा श्री हजूर साहिब जाएंगे और शहीदी समागम में सहभागिता के बाद हैदराबाद के लिए प्रस्थान करेंगे। रविवार के कार्यक्रम में दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, महाराष्ट्र की स्वास्थ्य राज्य मंत्री मेघना बोरदिकर, खाद्य एवं औषधि मंत्री नरहरि जिरवाल, कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरने और ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे सहित कई अन्य मंत्री और नेता भी मौजूद रहेंगे।

कुल मिलाकर नांदेड़ में आयोजित 'हिंद की चादर' शहीदी समागम केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास, संस्कृति और मूल्यों का जीवंत उत्सव बन गया है। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व पर उमड़ा यह जनसैलाब आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दे रहा है कि धर्म, मानवता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि सदियों तक समाज को दिशा देता रहता है।

शिक्षक पदों के मानदंडों में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी

(जीएनएस)। नई दिल्ली/मुंबई। शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के अधिकारों से जुड़ा एक अहम मामला सुप्रीम कोर्ट में चर्चा के केंद्र में आया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शिक्षक पदों के स्वीकृति मानदंडों में किए गए बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह मामला न केवल राज्य में शिक्षा नीति की दिशा तय करने वाला है, बल्कि पूरे देश में शिक्षक-छात्र अनुपात और शिक्षा की गुणवत्ता के महत्व को भी सामने लाता है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे शामिल हैं, ने सिंधुदुर्ग जिला शिक्षण संस्था चालक मंडल की याचिका पर राज्य सरकार, शिक्षा आयुक्त और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस भेजा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने 15 मार्च 2024 को जारी किया गया सरकारी आदेश (जीआर) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत निर्धारित विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात के खिलाफ है। इस आदेश के अनुसार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षक पदों को स्वीकृत करने के नियमों में बदलाव किया गया है।

याचिकाकर्ताओं का दावा है कि नए नियमों के तहत कई ऐसे विद्यालय बनेंगे, जहां छात्रों की संख्या कम होने पर भी केवल एक ही शिक्षक कई कक्षाओं के लिए जिम्मेदार होगा। इससे न केवल शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, बल्कि बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अधिवक्ता अजित प्रवीण वाघ ने अदालत में तर्क दिया कि यह बदलाव सीधे तौर पर शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन है और विद्यार्थियों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार में बाधा डालता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षक और छात्रों के बीच उचित अनुपात बनाए रखना शिक्षा की गुणवत्ता के लिए अनिवार्य है। अगर एक शिक्षक को कई कक्षाओं की जिम्मेदारी दी जाती है, तो बच्चों को समय और ध्यान पर्याप्त नहीं मिल पाता, और उनकी शैक्षणिक क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा, शिक्षक भी कई कक्षाओं के लिए जिम्मेदार होने के कारण अपने कर्तव्यों को पूरी तरह निभाने में असमर्थ हो सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की चिंता को गंभीरता से लिया है और सरकार से आदेश की वैधता और उसके प्रभावों पर स्पष्टीकरण मांगा है। अब यह मामला न्यायालय में आगे की सुनवाई के लिए तय किया जाएगा, और इसके निर्णय से महाराष्ट्र में शिक्षा नीति और शिक्षक नियुक्ति मानदंडों में बड़े बदलाव आने की संभावना है।

इस घटना ने शिक्षा जगत और समाज में भी बहस छेड़ दी है। शिक्षकों के संगठनों और अभिभावकों का मानना है कि शिक्षा का अधिकार केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों की भविष्य निर्माण की आधारशिला है। यदि शिक्षक पदों की संख्या छात्रों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार निर्धारित नहीं की जाती, तो यह बच्चों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ के समान होगा।

कुणाल कामरा की बढ़ी मुश्किलें, एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी मामले में दिल्ली कोर्ट का नोटिस, राजनीतिक व्यंग्य बनाम कानूनी दायरे की नई बहस

(जीएनएस)। नई दिल्ली/मुंबई। राजनीतिक व्यंग्य और सत्ता पर तीखे कटाक्षों के लिए पहचाने जाने वाले स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर कानूनी विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली की रोहिणी अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया है। इस घटनाक्रम के बाद न केवल राजनीतिक गलियारों में बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यंग्य की सीमाओं को लेकर भी नई बहस छिड़ गई है।

यह मामला शिवसेना (शिंदे गुट) के दिल्ली प्रदेश प्रमुख संदीप चौधरी की ओर से दायर क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुणाल कामरा ने 'नया भारत' शीर्षक वाले एक वीडियो में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया। याचिकाकर्ता का दावा है कि इस वीडियो के जरिए न केवल एक संवैधानिक पद पर बैठे नेता की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया, बल्कि इससे समाज में राजनीतिक वैमनस्य और तनाव फैलने की आशंका भी है।

रोहिणी कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज वंदना ने 20 जनवरी 2026 को इस मामले में सुनवाई के बाद कुणाल कामरा को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि कामरा को सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा। साथ ही, मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 मार्च तय की गई है। अदालत के इस आदेश के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और सभी की नजरें अब आने वाली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।

गौरतलब है कि यह वही मामला है जिसमें इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कुणाल कामरा को राहत दी थी। 15 सितंबर 2025 को मजिस्ट्रेट अदालत ने एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज करते हुए कहा था कि राजनीतिक व्यंग्य और पैरोडी को सीधे-सीधे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उस समय अदालत का यह भी कहना था कि कोई भाषा या टिप्पणी भले ही कुछ लोगों को अप्रिय लगे, लेकिन केवल इसी आधार पर उसे आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता, जब तक कि वह स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन न करे।

हालांकि, अब ऊपरी अदालत में रिवीजन पिटीशन स्वीकार किए जाने और नोटिस जारी होने से यह संकेत मिलता है कि न्यायालय इस मामले की कानूनी पहलुओं की नए सिरे से समीक्षा करना चाहता है। इससे यह सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विशेषकर व्यंग्य और हास्य के माध्यम से की गई राजनीतिक आलोचना, कहां तक वैध है और किस बिंदु पर वह कानून के दायरे में आ जाती है।

कुणाल कामरा इससे पहले भी कई बार अपने बयानों और प्रस्तुतियों के चलते विवादों में रहे हैं। वे अक्सर सत्ता, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर बेबाक टिप्पणी करते रहे हैं, जिसे उनके समर्थक लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रतीक मानते हैं, जबकि आलोचक इसे मर्यादा और सम्मान की सीमाओं का उल्लंघन बताते हैं। इस ताजा मामले ने एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि सार्वजनिक मंचों पर बोले गए व्यंग्य और कटाक्ष की कानूनी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए।

अब 20 मार्च को होने वाली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इस सुनवाई से यह तय हो सकता है कि क्या कुणाल कामरा के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुलेगा या फिर यह मामला फिर से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में किसी अहम टिप्पणी के साथ समाप्त होगा। जो भी फैसला आए, इतना तय है कि इसका असर केवल एक कॉमेडियन या एक नेता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह देश में राजनीतिक व्यंग्य और कानून के बीच की रेखा को और स्पष्ट करने वाला साबित हो सकता है।

साबरमती में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम कार्य के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल पर अहमदाबाद–विरमगाम रेलखंड में साबरमती ए केबिन (SBT-A) और साबरमती (SBT-E) के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम के कमीशनिंग कार्य हेतु 27 जनवरी, 2026 को प्रस्तावित ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी। इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

आंशिक रूप से निरस्त ट्रेनें

1.दिनांक 27.01.2026 की ट्रेन संख्या 20901/20902 मुंबई सेंट्रल–गांधीनगर कैपिटल-मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस अहमदाबाद और गांधीनगर कैपिटल के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

2.दिनांक 27.01.2026 की ट्रेन संख्या 22926 ओखा–अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस (01-ट्रिप) अपने निर्धारित मार्ग विरमगाम-साणंद-साबरमती(जेल साइड)-अहमदाबाद के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया विरमगाम-कटोसन रोड–कलोल-साबरमती बीजी के रास्ते चलेगी तथा साबरमती बीजी स्टेशन (धरमनगर साइड) पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा यह ट्रेन साबरमती बीजी(धरमनगर साइड) और अहमदाबाद के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। इस दौरान यह ट्रेन साणंद, साबरमती जं. (जेल साइड) और अहमदाबाद नहीं जाएगी।

पूर्णतः निरस्त ट्रेनें

1.दिनांक 26.01.2026 एवं 27.01.2026 की ट्रेन संख्या 69185 अहमदाबाद-विरमगाम मेमू निरस्त रहेगी।

2.दिनांक 27.01.2026 एवं 28.01.2026 की ट्रेन संख्या 69186 विरमगाम-अहमदाबाद मेमू निरस्त रहेगी।

3.दिनांक 26.01.2026 एवं 27.01.2026 की ट्रेन संख्या 22959 वडोदरा–जामनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

4.दिनांक 27.01.2026 एवं 28.01.2026 की ट्रेन संख्या 22960 जामनगर–वडोदरा इंटरसिटी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

5.दिनांक 27.01.2026 की ट्रेन संख्या 20959/20960 वलसाड–वडनगर-वलसाड इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

मार्ग परिवर्तित ट्रेनें

1.दिनांक 26.01.2026 को ट्रेन संख्या 19032 योग नगरी ऋषिकेश–साबरमती योगा एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग खोडियार-साबरमती बीजी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया खोडियार–चांदलोडिया–साबरमती 'ए' केबिन के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन साबरमती बीजी (धरमनगर साइड) के स्थान पर साबरमती स्टेशन (जेल साइड) पर जाएगी।

2.दिनांक 27.01.2026 की ट्रेन संख्या 14807 जोधपुर–दादर एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग खोडियार-साबरमती बीजी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया खोडियार–चांदलोडिया–साबरमती 'ए' केबिन–अहमदाबाद के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन साबरमती बीजी (धरमनगर साइड) के स्थान पर साबरमती स्टेशन (जेल साइड) पर ठहराव करेगी।

3.दिनांक 26.01.2026 की ट्रेन संख्या 14805 यशवंतपुर–बाड़मेर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग अहमदाबाद-साबरमती बीजी-खोडियार के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया अहमदाबाद–साबरमती 'ए' केबिन–चांदलोडिया–खोडियार के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन साबरमती बीजी (धरमनगर साइड) के स्थान पर साबरमती स्टेशन (जेल साइड) पर ठहराव करेगी।

4.दिनांक 27.01.2026 की ट्रेन संख्या 12216 बांद्रा टर्मिनस–दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीब रथ एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग अहमदाबाद-साबरमती बीजी (धरमनगर साइड)-खोडियार के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया अहमदाबाद–साबरमती 'ए' केबिन–चांदलोडिया–खोडियार के रास्ते चलेगी।

5.दिनांक 27.01.2026 की ट्रेन संख्या 11089 भगत की कोठी–पुणे एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग खोडियार-साबरमती बीजी (धरमनगर साइड) के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया खोडियार–चांदलोडिया–साबरमती 'ए' केबिन के रास्ते चलेगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करें। यात्री कृपया विस्तृत जानकारी हेतु रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन करें।

इंजीनियरिंग कार्य के चलते कानालुस–पोरबंदर और पोरबंदर–कानालुस लोकल ट्रेनों का संचालन 28 फरवरी तक गोप जाम स्टेशन से होगा

(जीएनएस)। राजकोट मंडल के कानालुस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म मरम्मत कार्य की वजह से 28 फरवरी, 2026 तक कानालुस–पोरबंदर और पोरबंदर–कानालुस लोकल ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार, प्रभावित ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:

आंशिक रूप से प्रभावित ट्रेनें

ट्रेन संख्या 59206 पोरबंदर–कानालुस लोकल

यह ट्रेन 26 जनवरी, 2026 से 28 फरवरी, 2026 तक पोरबंदर से प्रस्थान कर गोपजाम जाएगी तथा गोपजाम–कानालुस खंड के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

ट्रेन संख्या 59205 कानालुस–पोरबंदर लोकल

यह ट्रेन 26 जनवरी, 2026 से 28 फरवरी, 2026 तक कानालुस की बजाय गोपजाम स्टेशन से चलेगी और कानालुस-गोपजाम खंड के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

यात्रियों से निवेदन

रेल यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। ट्रेनों के परिचालन से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए यात्री वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।

तिरुपति लड्डू घी मिलावट कांड में सीबीआई की जांच पूरी, अंतिम चार्जशीट दाखिल होने से कई बड़े नाम घेरे में

(जीएनएस)। अमरावती। आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित विश्वप्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के प्रसाद लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी की मिलावट से जुड़े बहुचर्चित मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। मामले की जांच कर रही सीबीआई की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने अपनी विस्तृत जांच पूरी करते हुए स्थानीय अदालत में अंतिम चार्जशीट दाखिल कर दी है। सूत्रों के अनुसार यह चार्जशीट नेल्लोर की एसीबी अदालत में शुक्रवार को प्रस्तुत की गई, जिसमें तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) से जुड़े कुछ कर्मचारियों, घी आपूर्तिकर्ताओं और अन्य संबंधित व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में सामने आए तथ्यों ने इस पूरे मामले की गंभीरता को और स्पष्ट कर दिया है। जांच में पाया गया है कि श्रद्धालुओं की आस्था से सीधे जुड़े प्रसाद निर्माण में इस्तेमाल होने वाले घी में जानबूझकर मिलावट की गई थी। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, शुद्ध देसी घी के स्थान पर उसमें पाम ऑयल, पाम कर्नेल ऑयल और पामोलीन जैसे सस्ते और निम्न गुणवत्ता वाले तेलों की मिलावट की गई। इतना ही नहीं, इस मिलावट को छिपाने और जांच एजेंसियों तथा प्रयोगशालाओं को गुमराह करने के लिए रासायनिक पदार्थों का भी इस्तेमाल किया गया। सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया है कि मिलावटी घी में बीटा कैरोटीन, एसीटिक एसिड एस्टर, घी फ्लेवर और अन्य कृत्रिम रसायन मिलाए गए थे, ताकि लेबोरेटरी टेस्ट में फैट वैल्यू और अन्य मानक सही प्रतीत हों और घी की खुशबू भी असली जैसी बनी रहे। जांच एजेंसी का मानना है कि यह एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें गुणवत्ता से समझौता कर आर्थिक लाभ कमाने का प्रयास किया गया और इसके लिए धार्मिक आस्था को भी नजरअंदाज किया गया।

सूत्रों के अनुसार, चार्जशीट में यह भी उल्लेख किया गया है कि घी की आपूर्ति प्रक्रिया में कई स्तरों पर लापरवाही और मिलीभगत देखने को मिली। सप्लाई चेन में शामिल कुछ लोगों ने जानबूझकर गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की, जबकि कुछ टीटीडी कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने जांच और निरीक्षण की प्रक्रिया में आंख मूंद ली या फिर जानबूझकर खामियों को नजरअंदाज किया।

सोना वायदा में 13220 रुपये और चांदी वायदा में 35712 रुपये का ऊछाल: क्रूड ऑयल में 74 रुपये की तेजी

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 16 से 22 जनवरी के सप्ताह के दौरान कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 3650128.21 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 799478.98 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 2850540.39 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 42989 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 74319.18 करोड़ रुपये का हुआ। आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 671344.78 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 142589 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 158475 रुपये के उच्च और 141220 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 143121 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 13220 रुपये या 9.24 फीसदी की तेजी के संग 156341 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-गिनी जनवरी वायदा सप्ताह के अंत में 13720 रुपये या 11.8 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 129968 रुपये प्रति 8 ग्राम पर बंद हुआ। गोल्ड-पेटल जनवरी वायदा 1705 रुपये या 11.72 फीसदी की तेजी के संग सप्ताह के अंत में 16247 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 142415 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 158780 रुपये के उच्च और 141184 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 13683 रुपये या 9.58 फीसदी की मजबूती के साथ 156533 रुपये प्रति 10 ग्राम बंद हुआ। गोल्ड-टेन जनवरी वायदा प्रति 10 ग्राम सप्ताह के आरंभ में 143131 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 159500 रुपये के उच्च और 142000 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 143406 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 13412 रुपये या 9.35 फीसदी की बढ़त

▶▶ कमोडिटी वायदाओं में 799478 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 2850540 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ साप्ताहिक टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 671344 करोड़ रुपये का हुआ साप्ताहिक कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 42989 पॉइंट के स्तर पर

के साथ 156818 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 287127 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 335521 रुपये और नीचे में 284045 रुपये पर पहुंचकर, 291577 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 35712 रुपये या 12.25 फीसदी बढ़कर 327289 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 38972 रुपये या 13.28 फीसदी की तेजी के संग 332393 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 38936 रुपये या 13.26 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 332476 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ।

मेटल वर्ग में 41367.59 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा जनवरी वायदा सप्ताह के अंत में 35.45 रुपये या 2.71 फीसदी की औंधकर 1273.05 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ। जबकि जस्ता जनवरी वायदा 5.9 रुपये या 1.86 फीसदी लुढ़ककर 311.95 रुपये प्रति किलो सप्ताह के अंत में बंद हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा सप्ताह के अंत में 3.5 रुपये या 1.1 फीसदी घटकर 315.2 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। जबकि सीसा जनवरी वायदा सप्ताह के अंत में 1.85 रुपये या 0.96 फीसदी घटकर 190.15 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 86732.20 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा 5357 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 5607 रुपये और नीचे में 5345 रुपये पर पहुंचकर, सप्ताह के अंत में 74 रुपये या 1.38 फीसदी की तेजी के संग 5440 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 74 रुपये या 1.38 फीसदी की बढ़त के साथ 5442 रुपये प्रति बैरल के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा 246 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 341 रुपये और नीचे में 241.4 रुपये पर पहुंचकर, 244.4 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 82 रुपये या 33.55 फीसदी की तेजी के संग 326.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 81.2 रुपये या 33.21 फीसदी की मजबूती के साथ 325.7 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बंद हुआ।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल जनवरी वायदा 970 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के अंत में 14.7 रुपये या 1.51 फीसदी औंधकर 958.7 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सप्ताह के दौरान सोना के विभिन्न अनुबंधों में 352891.38 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 318453.40 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 35332.99 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 2745.79 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 357.36 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 2815.32 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 7029.96 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 79615.75 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 30.04 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 1.32 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

सप्ताह के अंत में ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 11402 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 39495 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 6092 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 69441 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 15754 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 9745 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 23106 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 48598 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 14671 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 12489 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 38950 पॉइंट पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 44301 के उच्च और 38700 के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 4176 पॉइंट बढ़कर 42989 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ।